WWW.NAVPRADESH.COM

दैनिक

नव प्रदेश

प्रदेश के साथ पूरा देश...

अंदर के पृष्ठों पर... 2 | देश विदेश 4 | अभिव्यक्ति 5 | आस-पास 7 | खेल/ बिजनेस

RNI NO - MPHIN/2020 /81503 जबलपुर, गुरूवार 27 नवंबर 2025 , शुक्ल पक्ष षष्ठी, विक्रम संवत -2082 , वर्ष -5 अंक - 116 पृष्ठ -08 मूल्य-4 रूपए जबलपुर, भोपाल, रायपुर, बिलासपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी, अहमदाबाद में होंगे गेम्स

ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक में आईओए की प्रेसिडेंट पीटी ऊषा ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में किया साइन

ओलिंपिक गेम्स 2036 की दावेदारी मजबूत होगी

नई दिल्ली/ए.। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिल गई है। बुधवार को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक के बाद अहमदाबाद को होस्ट सिटी घोषित किया गया। भारत 15 साल के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2010 में नई दिल्ली इन गेम्स का आयोजन किया गया था। तब भारतीय खिलाड़ियों ने 38 गोल्ड समेत 101 मेडल जीते थे।

कॉमनवेल्थ की टीम दो बार गुजरात का दौरा कर चुकी: अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के आयोजन के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यहां खिलाड़ियों, अधिकारियों और दर्शकों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्य ■ शेष पृष्ठ 6

20 साल बाद भारत में कोई मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट

- 20 साल के बाद भारत में कोई मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट होने जा रहा
- पहले 2010 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन
- सीडब्ल्यूसी के अलावा, भारत 1951 और 1982 एशियन गेम्स की मेजबानी कर चुका
- 2003 में हैदराबाद में एफ्रो-एशियन कप का आयोजन भी हुआ था

ओलिंपिक-2036 की दावेदारी मजबूत होगी

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने से ओलिंपिक गेम्स 2036 की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी मजबूत होगी। भारत 2036 के ओलिंपिक गेम्स की मेजबानी की तैयारी भी कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की से इसका ऐलान किया था। पिछले साल नवंबर में भारत ने ओलिंपिक गेम्स-2036 की मेजबानी हासिल करने के लिए दावेदारी पेश की थी।

अहमदाबाद के अलावा अबुजा भी था दौड़ में शामिल

पिछले महीने राष्ट्रमंडल खेल कार्यकारी बोर्ड ने अहमदाबाद में इन खेलों के आयोजन की सिफारिश की थी। अब ग्लास्गो में हुई आमसभा की बैठक में इसे अंतिम मंजूरी मिल गई है। अहमदाबाद के अलावा नाइजीरिया का अबुजा मेजबानी की दौड़ में शामिल था, लेकिन भारत बाजी मारने में सफल रहा। राष्ट्रमंडल खेल को 2030 में 100 साल भी पूरे होने जा रहे हैं, ऐसे में इस ऐतिहासिक मौके पर भारत में इन खेलों का आयोजन होना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है।

आज बेबाक

बंगाल में एसआईआर से वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बौरा गई हैं। वहां से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए डर कर भाग रहे हैं। इससे ममता दीदी का वोट बैंक खत्म हो रहा है और उनकी राजनीतिक दुकानदारी के बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। नतीजतन दीदी अब दादागिरी पर उतर आई है। उन्होंने सीधे केन्द्र सरकार को धमकी दी है कि एसआईआर से उनके वोट बैंक पर आंच आई तो वे पूरे भारत देश को हिलाकर रख देंगी। इस तरह की गीदड़भभकी देने वाली दीदी यह समझ लें कि भीगी बिल्लियों के छींकने से पहाड़ नहीं गिरा करते।

राज्य वीरता पुरस्कार: बहादुर बच्चों को छत्तीसगढ़ सराकर देगी 25 हजार नकद इनाम

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के बच्चों को किसी विशेष घटना में प्रदर्शित उनके अदम्य साहस, बुद्धिमत्ता और वीरता के सम्मान में 'राज्य वीरता पुरस्कार वर्ष 2025' प्रदान करने जा रही है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 5 बालक/बालिकाओं को 25 हजार रुपए नकद राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार से संबंधित ज्यादा जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, जी. ई. रोड, रायपुर स्थित कार्यालय के सूचना पटल पर 20 दिसंबर तक देखी जा सकती है। इच्छुक आवेदक अपनी प्रविष्टियां 20 दिसंबर 2025 तक जिला कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग में प्रस्तुत कर सकते हैं।

कमला पसंद कंपनी के मालिक की बहू ने आत्महत्या की

नई दिल्ली/ए.। देश की मशहूर पान मसाला कंपनी कमला पसंद और राजश्री के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया (38) ने दिल्ली के वसंत विहार स्थित अपने घर में मंगलवार शाम आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार दीप्ति का शव ड्रेसिंग रूम के पंखे से लटका हुआ मिला। दीप्ति का शव सबसे पहले उसके पति हरप्रीत चौरसिया ने देखा। हरप्रीत उन्हें लेकर अस्पताल गए, जहां दीप्ति को मृत घोषित कर दिया गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक, पुलिस को एक डायरी मिली है, जिसमें दीप्ति ने अपने पति के साथ विवाद का जिक्र किया है। दीप्ति ने डायरी में लिखा, 'अगर किसी रिश्ते में प्यार और भरोसा नहीं तो फिर उस रिश्ते में रहने की और जीने की वजह क्या है।

विदेश भेजने वाले पैसे से 10% से ज्यादा नहीं काट सकते टीडीएस :सुको

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित देश के साथ भारत का डबल टैक्स एडवांस एग्रीमेंट है तो अनिवासी भारतीय या विदेशी कंपनियों को भेजी जाने वाली धनराशि पर टीडीएस 10% से अधिक काटा जा सकता। यह फैसला उन मामलों पर लागू होगा, जहां विदेशी प्राप्तकर्ता डीटीएए के लाभ लेने के योग्य हैं। अदालत ने कहा कि यदि डीटीएए में अधिकतम टैक्स 10' तय है, तो आयकर विभाग 20' टीडीएस की मांग नहीं कर सकता भले ही विदेशी कंपनी या प्राप्तकर्ता ने पैन उपलब्ध न कराया हो।

केन्द्रीय कैबिनेट : दुर्लभ धातुओं पर सरकार का बड़ा कदम

मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने 7,280 करोड़ की मंजूरी

नई दिल्ली/आईएएनएस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कुल 19,919 करोड़ रुपये की चार बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसमें 7,280 करोड़ की दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट निर्माण योजना शामिल है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा क्षेत्र के लिए अहम मानी जा रही है।

इसके अलावा, पुणे मेट्रो विस्तार के लिए 9,858 करोड़, देवभूमि द्वारका (ओखा)-कनालस रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए 1,457 करोड़ और बदलापुर-कर्जत तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के लिए 1,324 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

दुर्लभ मृदा स्थायी चुम्बक योजना के लिए 7,280 करोड़

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को होने वाली बैठक में दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए करीब 7,280 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है, जो पहले के 2,500 करोड़ रुपये के अनुमानित पैकेज से लगभग तीन गुना अधिक है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब चीन ने निर्यात नियंत्रण कड़े कर दिए हैं। चीन वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी कच्चे माल का 60-70%और प्रोसेसिंग का 90% हिस्सा नियंत्रित करता है।

चीन का दबाव और भारत की रणनीति

एक रिपोर्ट के अनुसार चीन ने भारत में उपयोग के लिए दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट के निर्यात के शुरुआती लाइसेंस जारी किए हैं, लेकिन भारतीय कंपनियों को अब तक कोई लाइसेंस नहीं मिला है। भारत की वार्षिक मांग लगभग 2,000 टन ऑक्साइड की है, इसे पूरा करने के लिए कई वैश्विक सप्लायर रुचि दिखा रहे हैं। सरकार सिक्रोनस रिलक्टेंस मोटर्स पर अध्ययन को फंड कर रही है, ताकि भविष्य में दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के मामले में देश के बाहर से होने वाले आयात पर निर्भरता कम की जा सके।

क्यों है यह योजना अहम?

केंद्रीय सरकार ने दुर्लभ मृदा स्थायी चुम्बक निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह की पहली योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य सिंटर किए गए आरईपीएम के उत्पादन के लिए एकीकृत विनिर्माण सुविधाएं विकसित करना है, जिसमें दुर्लभ मृदा ऑक्साइड को धातुओं में, धातुओं को मिश्रधातुओं में और आखिर में मिश्रधातुओं को तैयार चुम्बकों में बदलने की प्रक्रिया शामिल होगी। योजना पर लगभग 7,200 करोड़ का निवेश होगा। इसके तहत 1,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता का सृजन और 1,200 एमटीपीए क्षमता वाली इकाइयों की स्थापना की जाएगी। योजना की अवधि कुल 7 वर्ष होगी, जिसमें विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 2 वर्ष का समय निर्धारित है। दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा उत्पादन में होता है। भारत में इस क्षेत्र को अभी पर भी सीमित फंडिंग, ■ शेष पृष्ठ 6

इन परियोजनाओं को हरी झंडी

- 7,280-रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट निर्माण योजना
- 1,457-देवभूमि द्वारका (ओखा) - कनालस रेलवे लाइनकादोहरीकरण
- 9,858-पुणे मेट्रो का विस्तार
- 1,324- बदलापुर - कर्जत तीसरी और चौथी रेलवे लाइन

19,919-सभी परियोजनाओं पर कुल आवंटन, राशि आवंटन (करोड़)

किसानों की खुशहाली और समृद्धि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गौतमपुरा से 1.34 लाख किसानों के खातों में अंतरित की 249 करोड़ रूपए भावांतर राशि

गौतमपुरा में खुलेगा महाविद्यालय, पीएचसी अब सीएचसी में होगा अपग्रेड

मुख्यमंत्री, किसानों को भावांतर राशि वितरण और विकास कार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम में हुए शामिल

भोपाल/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं। वे तरह-तरह के जोखिम उठाकर समाज और देश के लिए अन्न-धन का भंडार भरते हैं। प्रकृति की मार सहकर और खुद के दाना-पानी की चिंता में न रहकर सबका उदर पोषण करते हैं। उन्होंने कहा कि सीमा पर जवान और खेतों में हमारे किसान दोनों समान रूप से राष्ट्र की सेवा में तत्पर रहते हैं। किसान भाइयों के घर-आंगन में खुशहाली और आर्थिक समृद्धि लाना ही हमारी सरकार का मूल लक्ष्य है। हम प्रदेश के हर किसान को उसके द्वारा उत्पादित फसल का समुचित दाम दिलाएंगे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को इंदौर जिले के गौतमपुरा में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोयाबीन की फसल पर भावान्तर भुगतान योजना के तहत प्रदेश के 1.34 लाख पात्र किसानों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 249 करोड़ रुपये अंतरित किये। अब तक प्रदेश के 4.39 लाख से अधिक किसानों द्वारा 7.85 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन फसल का विक्रय किया ■ शेष पृष्ठ 6 पर

माओवाद को बड़ा झटका, 41 कैडरों ने छोड़ी बंदूक, मुख्यधारा में लौटे

आत्मसमर्पण करने वालों में कई बड़े नाम

पीएलजीए बटालियन-1 के 5 सदस्य, 3 एरिया कमेटी मेंबर, कई प्लाटून कमांडर, मिलिशिया कमांडर और जनताना सरकार के बड़े पदाधिकारी शामिल है।

बीजापुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में बुधवार को माओवादियों को करारा झटका लगा। कुल 41 माओवादी कैडरों ने हथियार डाल दिए और समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। इन पर कुल 1 करोड़ 19 लाख रुपये का इनाम था। इनमें 12 महिलाएं और 29 पुरुष हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में कई बड़े नाम शामिल हैं। इनमें पीएलजीए बटालियन-1 के 5 सदस्य, 3 एरिया कमेटी मेंबर, कई प्लाटून कमांडर, मिलिशिया कमांडर और जनताना सरकार के पदाधिकारी हैं। ज्यादातर (39) दक्षिण सब-जोनल ब्यूरो के हैं, जबकि कुछ तेलंगाना स्टेट कमेटी और धमतरी-गरियाबंद-नुआपाड़ डिवीजन से भी हैं। सबसे बड़े इनामी कैडरों में पति-पत्नी पण्डरू हपका उर्फ मोहन और बण्डी हपका शामिल हैं, ■ शेष पृष्ठ 6

उज्जैन से होने वाला प्रसारण आकाशवाणी के इतिहास में लिखेगा नई इबारत : सीएम यादव

मुख्यमंत्री ने किया उज्जैन के आकाशवाणी केन्द्र का लोकार्पण

आकाशवाणी का उज्जैन केन्द्र बनेगा युवाओं के रोजगार और प्रसारण कौशल का जरिया- केन्द्रीय राज्यमंत्री डॉ. मुरूगन

प्रदेश का 20वां आकाशवाणी केन्द्र है उज्जैन

भोपाल/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि यह आकाशवाणी का उज्जैन केन्द्र है, ऐसा सुनने की हसरत अब जाकर पूरी हुई है। आकाशवाणी का भवन तैयार था, परंतु प्रसारण की मंजूरी के कारण अटका था। मंजूरी मिलने के मात्र 6 माह में उज्जैन के आकाशवाणी केंद्र से प्रसारण प्रारम्भ हो गया है। यह प्रदेश का 20वां आकाशवाणी केन्द्र है। इस केंद्र से निकले एक-एक शब्द उज्जैन और सिंहस्थ की प्रतिष्ठा होंगे। आकाशवाणी के कार्यक्रम, इसकी प्रस्तुति गांव-गांव तक उज्जैन और सिंहस्थ की महिमा पहुंचाएगी। मुझे विश्वास है कि आकाशवाणी अपना यह दायित्व, पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मनोरंजन के साथ आकाशवाणी ने समाज सेवा और जन-जागरूकता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उज्जैन से होने वाला प्रसारण आकाशवाणी के इतिहास में नई इबारत लिखकर चार चांद लगाएगा। यहां रोजाना सुबह 5.55 बजे से ■ शेष पृष्ठ 6 पर

संविधान राष्ट्रीय अस्मिता का ग्रंथ, विश्व के लिए उदाहरण: राष्ट्रपति मुर्मु

भारतीय संसद, विश्व के अनेक लोकतंत्रों के लिए उदाहरण

नई दिल्ली(वार्ता)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संविधान को राष्ट्रीय अस्मिता और पहचान का ग्रंथ बताते हुए कहा है कि बीते दशक में हमारी संसद ने इसके मूल्यों पर चलते हुए जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने के अनेक कार्य किये हैं। मुर्मु ने बुधवार को यहां संविधान दिवस के अवसर पर संविधान सदन के केन्द्रीय कक्ष में अपने अभिभाषण में कहा कि संविधान सभा ने संसदीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में जो ठोस तर्क दिये गए थे वे आज भी प्रासंगिक हैं। विश्व के विशालतम लोकतन्त्र में जन-आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने वाली भारतीय संसद, विश्व के अनेक लोकतंत्रों के लिए आज एक उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित है। उन्होंने कहा ,' हमारे संविधान निर्माता ■ शेष पृष्ठ 6

संविधान दिवस: मोदी ने नागरिकों से अपने कर्तव्यों को सबसे पहले रखने पर दिया जोर

भारत अब 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा

नई दिल्ली (वार्ता)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को संविधान दिवस के मौके पर नागरिकों से अपील की कि वे अपने कर्तव्यों को सबसे पहले रखें क्योंकि भारत अब एक 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। श्री मोदी ने संविधान दिवस के अवसर पर देश के नागरिकों को पत्र लिखकर 1949 में संविधान को ऐतिहासिक रूप से अपनाए जाने का स्मरण करते हुए राष्ट्र की प्रगति में इसकी स्थायी भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में सरकार ने इस पवित्र दस्तावेज के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था। श्री मोदी ने इस बात का उल्लेख किया कि कैसे संविधान ने साधारण पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को उच्चतम स्तर पर ■ शेष पृष्ठ 6

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल अद्वितीय और विराट व्यक्तित्व के धनी : सीएम यादव

नर्मदा प्रवाह यात्रा यूनिटी मार्च का हुआ भव्य स्वागत

इंदौर से धार-झाबुआ होते हुए गोधरा के लिए रवाना हुई यात्रा

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का पुष्प वर्षा के साथ हुआ स्वागत

भोपाल/नवप्रदेश। लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित नर्मदा प्रवाह यूनिटी मार्च यात्रा का बुधवार को इंदौर में अगवानी कर स्वागत किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में यात्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रतिमा से शुरू होकर मधुमिलन चौराहा, आरएनटी मार्ग होते हुए छावनी चौराहा पहुँची। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री ■ शेष पृष्ठ 6 पर

नक्सल पुनर्वास केंद्र सुकमा में 25 लोगों को बांटे गए 5जी स्मार्टफोन

■ आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिला नया जीवन पथ

■ 25 आत्मसमर्पित नक्सलियों को मिला 5जी स्मार्टफोन

■ डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सुकमा दौरे के दौरान आधुनिक 5जी मोबाइल उपलब्ध कराने के दिए थे निर्देश

सुकमा/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण 5जी स्मार्टफोन बांट रही है। इसी कड़ी में पुनर्वास एवं मुख्यधारा से जुड़ने के सरकारी प्रयासों को मज़बूती देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के मार्गदर्शन में पुनर्वास केंद्र सुकमा में 25 आत्मसमर्पित नक्सलियों को उच्च गुणवत्तापूर्ण 5जी स्मार्टफोन प्रदान किए गए। यह वितरण कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव, एसपी किरण चव्हाण के मार्गदर्शन में किया गया।

गौरतलब है कि, 22 नवंबर को अपने सुकमा प्रवास के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पुनर्वास केंद्र में रह रहे सभी लोगों को आधुनिक 5जी मोबाइल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे, ताकि वे तकनीकी रूप से सशक्त बन सकें और समाज की मुख्यधारा में सुगमता से जुड़ सकें।

इसी कड़ी में मंगलवार को डिप्टी कलेक्टर मधु तेता एवं डीएसपी मोनिका श्याम द्वारा 25 पुनर्वासित युवाओं को सैमसंग गैलेक्सी एम06 5जी मोबाइल प्रदान किए गए, जिनमें 50 मेगापिक्सल डुअल कैमरा तथा 5000 एमएएच की फास्ट-चार्जिंग सपोर्ट बैटरी जैसी उन्नत विशेषताएँ मौजूद हैं।

इस पहल से पुनर्वास प्रक्रिया में मिलेगी मदद

इस पहल को नक्सलवाद विरोधी अभियान में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य पुनर्वासित व्यक्तियों को न केवल समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है, बल्कि उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार करना भी है। अब ये आत्मसमर्पित व्यक्ति ऑनलाइन शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। यह उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों, छोटे व्यवसाय शुरू करने की विधियों और अन्य स्वरोजगार के अवसरों को तलाशने में मदद करेगा। यह पुनर्वास प्रक्रिया को न केवल व्यावहारिक बल्कि मानवीय स्पर्श भी प्रदान करता है।

जो बच गए उन्हें भी जल्द मिलेगा स्मार्ट फोन

जिला प्रशासन के द्वारा बताया गया कि, शेष पुनर्वासित लोगों को भी शीघ्र ही 5जी स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। यह पहल न केवल बेहतर संचार और तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराएगी, बल्कि इन युवाओं को रोजगार, शिक्षा एवं सरकारी योजनाओं से जुड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

संत ज्ञानेश्वर के बच्चों ने जीता बेस्ट क्राफ्टमेनशिप अवार्ड

रायपुर/नवप्रदेश। कलिंगा विश्वविद्यालय में बीते दिनों आयोजित साइंस वर्किंग मॉडल प्रतियोगिता 4.0 में एयर पॉल्यूशन और फ्लोइजी का वर्किंग मॉडल बनाकर महाराष्ट्र मंडल द्वारा संचालित संत ज्ञानेश्वर विद्यालय बेस्ट क्राफ्ट मेनशिप अवार्ड अपने नाम कर लिया बतादें कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों को वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझते हुए कार्यात्मक मॉडल तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करना था। प्रतियोगिता में प्रस्तुत मॉडल वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों, नवाचारी सोच और वर्तमान चुनौतियों के रचनात्मक समाधानों पर आधारित थे। विभिन्न विभागों के छात्र पर्यावरण, सतत विकास, कृषि, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, सामुदायिक कल्याण और सामाजिक विकास जैसे विविध विषयों पर अपने मॉडल प्रदर्शित किया। स्कूल की शिक्षिका रीता संभलकर ने बताया कि कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा साइंस वर्किंग मॉडल प्रतियोगिता 4.0 का आयोजन बीते दिनों किया गया था। जिसमें हमारे विद्यालय की दो टीम ने हिस्सा लिया था। पहली टीम में दीपिका अग्रवाल और प्रियंका सोनवानी शामिल थीं। इन्होंने अपने मॉडल एयर पॉल्यूशन पर प्रस्तुत किया। दूसरी टीम में गौरांश साहू, पूर्वी साहू और वर्षा परीडा शामिल थे। इन्होंने अपने नवाचारी मॉडल फ्लोइजी को प्रस्तुत किया। इस मॉडल ने प्रतियोगिता में बेस्ट क्राफ्ट मेनशिप अवार्ड जीता। इस टीम को 5000 रुपये की नकद राशि और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। कलिंगा विश्वविद्यालय के कुलपति ने स्नद्यश्2श्वड्डह्यद्द मॉडल की विशेष सराहना की और घोषणा की कि उनकी टीम हमारे विद्यार्थियों की इस मॉडल का पेटेंट दर्ज कराने में सहायता करेंगे। बच्चों को स्कूल की शिक्षिक नीदा सुल्तान लेकर गई थी।

नियमों की अनदेखी पर उठे गंभीर सवाल !

धान घोटाले के आरोपी कर्मचारी को फिर मिली जिम्मेदारी

कोरिया/नवप्रदेश। सुराजपुरब जिले में धान खरीदी और परिवहन व्यवस्था में करोड़ों रुपए के गबन और अनियमितताओं का आरोप झेल चुके कंप्यूटर ऑपरेटर दीपेश साहू को कोरिया जिले के धान खरीदी समिति जामपारा में नियुक्ति का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। सूरजपुर जिले के विस्तृत जांच रिपोर्टों में सामने आए धांधली के तथ्य, धान की फर्जी एंट्री, परिवहन आदेशों में हेराफेरी और सरकारी खाद्यान्न के गबन के बावजूद दीपेश साहू को बैकुंठपुर जामपारा समिति में दोबारा पदस्थ कर दिया गया है। इस निर्णय ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर नियमों को दरकिनार कर किस आधार पर ऐसे कर्मचारी को दोबारा जिम्मेदारी दी जा रही है।

जांच प्रतिवेदन के अनुसार सूरजपुर जिले में धान परिवहन और संग्रहण केंद्रों में 2017 से लेकर 2020 तक विभिन्न केंद्रों पर भारी अनियमितताएँ पाई गईं। कई मौकों पर धान की एंट्री एक ही दिन में दो-दो बार की गई, ट्रकों की फर्जी रसीदें बनाकर धान को कहीं और भेजा गया, तथा वास्तविक स्टॉक और ऑनलाइन रिपोर्ट में भारी अंतर पाया गया। रिपोर्टों के अनुसार 18,95,62,900 रुपए का धान कम पाया गया, जबकि कुल गड़बड़ी की राशि लगभग 20 करोड़ से अधिक आंकी गई है।इतने बड़े घोटाले में दीपेश साहू की भूमिका जांच में प्रमाणित होने के बावजूद, उसे निलंबित करने या सेवा से पृथक करने के बजाय पुनः जिम्मेदारी सौंप दी गई। यह निर्णय न केवल शासन के नियमों के विपरीत है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि विभागीय स्तर पर गंभीर अनियमितताओं को किस तरह दबाया जा रहा है।

क़ानून विशेषज्ञों के अनुसार, सरकारी खाद्यान्न के गबन या फर्जीवाड़े के मामलों में भारतीय दंड संहिता (ढ्ढक्क्ष्ट) की धारा 409 (लोकसेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात), धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 467-468 (फर्जी दस्तावेज तैयार करना), तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 लागू होती हैं। इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने वाले अधिकारी या कर्मचारी को न केवल सेवा से निलंबित किया जाता है, बल्कि विभाग में पुनः पदस्थ करने पर पूर्ण प्रतिबंध होता है।

इसके बावजूद विभाग द्वारा दीपेश साहू को कोरिया जिले के जामपारा समिति में फिर से नियुक्त करना यह दर्शाता है कि या तो मामले को हल्के में लिया जा रहा है, या फिर किसी राजनीतिक अथवा प्रशासनिक दबाव में निर्णय लिया गया है।स्थानीय किसानों और सामाजिक संगठनों ने इस निर्णय पर कड़ा विरोध दर्ज करते हुए कहा है कि जब करोड़ों की गड़बड़ियां सामने हैं तो ऐसे कर्मचारी को पुनः जिम्मेदारी देना सरकारी तंत्र पर अविश्वास की स्थिति पैदा करता है।

मंत्रालयीन अधिकारियों को भारत के संविधान उद्देशिका का कराया सामूहिक वाचन

रायपुर/नवप्रदेश।मुख्य सचिव श्री विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रालय के अधिकारी और कर्मचारियों को आज 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान की उद्देशिका का सामूहिक रूप से वाचन कराया। मुख्य सचिव ने भारत के संविधान की उद्देशिका का वाचन कराया कि ''हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई. को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है।''इस मौके पर मुख्य सचिव ने भारत के संविधान की उद्देशिका के महत्व पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुआ, माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, प्रमुख सचिव विधि विभाग श्रीमती सुषमा सावंत, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी.दयानंद, नगरीय प्रशासन एवं मुख्यमंत्री के सचिव श्री बसवराजू एस.,सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए।

अयोध्या के लिए श्रद्धालुओं का जत्था रवाना

■ नगरी के 31 भक्त रामलला दर्शन के लिए रवाना

नगरी/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के नगरी से रामलला दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान पूरा माहौल श्रीराम के नारों से गुंजायमान हो उठा। कुल 31 रामभक्तों की टोली विशेष रूप से व्यवस्था की गई बस से रायपुर जायेंगे। इसके बाद सभी श्रद्धालु विशेष तीर्थयात्रा ट्रेन से अयोध्या धाम पहुँचेंगे। जहां पर वे भगवान श्री रामलला के दर्शन करेंगे। वहीं चार दिवसीय पवित्र यात्रा में अयोध्या के साथ ही काशी और अन्य तीर्थ स्थलों के दर्शन करेंगे। रवानगी से पहले सभा हाल में सभी श्रद्धालुओं का आरती उतारकर पारंपरिक रूप से सम्मान किया गया। आयोजन स्थल पर उत्साह, भक्ति और आनंद का ऐसा वातावरण था कि, हर कोई भावविभोर दिखाई दिया। समाज के वरिष्ठजनों और पदाधिकारियों ने अपनी शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि, यह तीर्थयात्रा न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करेगी, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी संदेश देगी। भक्ति, उल्लास और राम नाम के जयघोषों के बीच श्रद्धालुओं का जत्था अपनी पावन यात्रा पर प्रस्थान कर गया।

बाबा काशी विश्वनाथ के भी करेंगे दर्शन

इस चार दिवसीय धार्मिक यात्रा में श्रद्धालु न केवल अयोध्या राम मंदिर की दिव्य अनुभूति प्राप्त करेंगे, बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर, हनुमान मंदिर तथा अन्य महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थलों के भी दर्शन करने का सौभाग्य पाएंगे। धार्मिक उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर यह जत्था आगामी 30 तारीख को नगरी लौटेगा।

सड़क निर्माण में हुई गड़बड़ी को लेकर सीएम से की गई शिकायत

रायगढ़/नवप्रदेश। गांव में आधी-अधूरी सीसी सड़क निर्माण कर लाखों रुपए डकारने की शिकायत ग्रामीणों ने सीएम जनदर्शन में की है। ग्रामीणों ने शिकायत में बताया है कि सितंबर माह में काम पूरा बताकर राशि निकाल लिया है। जबकि जितने दूरी के लिए सड़क निर्माण होना था उतना हुआ ही नहीं है। उक्त मामला खरसिया के ग्राम मौहापाली की है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार खरसिया ब्लॉक अंतर्गत मौहापाली के ग्रामीणों ने सीएम जनदर्शन में शिकायत करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत मौहापाली में 2024-25 में सांसद मद से 8 लाख बदन घर से जीतराम घर तक सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत हुआ था। जिसमें निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत मौहापाली है। उन्होने आरोप लगाया है कि सड़क निर्माण में एजेंसी द्वारा अनियमितता बरतते हुए कुछ मीटर ही सड़क का निर्माण किया गया है। साथ ही15 सितंबर 2025 को सड़क को पूर्ण बताते हुए राशि का आहरण कर लिया गया है। इसी तरह मौहापाली में ही 2024-25 में देवस्थल से नाला पार तक सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए 15 वें वित्त से 6 लाख की राशि स्वीकृत हुआ था। जिसे ग्राम पंचायत मौहापाली एजेंसी ने कराया है।16 सितंबर को सड़क पूरा बता दिया गया है, मगर सड़क आधा-अधूरा है। ऐसे में ग्रामीणों ने इसकी लिखित शिकायत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।

बैंक खातों के जरिए साइबर फ्रॉड का खुलासा, 16 गिरफ्तार

भिलाई/नवप्रदेश। मोहन नगर पुलिस ने साइबर ठगी में उपयोग किए जा रहे म्यूल अकाउंट के बड़े फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ करते हुए 16 खाताधारकों को गिरफ्तार किया है। इन खातों का इस्तेमाल देशभर में सक्रिय साइबर ठगों ने धोखाधड़ी से अर्जित राशि को खपाने और आगे बढ़ाने के लिए किया था।

एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि कार्रवाई भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के समन्वय पोर्टल से मिले इनपुट के आधार पर की गई। पोर्टल से मिली जानकारी में कर्नाटक बैंक, मोहन नगर शाखा के 22 खातों में करीब 11 लाख रुपए की संदिग्ध राशि जमा पाए जाने की बात सामने आई थी।

जांच में पुष्टि हुई कि ये रकम विभिन्न ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग और साइबर ठगी गतिविधियों से प्राप्त की गई थी, जिसे खाताधारकों ने निकाला, खर्च किया या अन्य खातों में ट्रांसफर कर आगे बढ़ाया।

सभी आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने व्यापक तलाश के बाद कलविंदर सिंह, चौहान जीवन, निधि बघेल, लालकृष्ण साहू, राहुल यादव, पंकज चौबे, अक्षय सोनी, पायल सोनी, राज सिंह, राहुल कुमार जयसेल, उज्जवल सिंह, पंकज टंडन, हेमंत दलाई, रामअवतार यदु, मुकुंद सेन और राम दुबे को गिरफ्तार किया। सभी के खिलाफधारा 317(2), 317(4), 318(4), 111, 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

कैसे काम करता था गैंग?

एएसपी ने बताया कि आरोपी थोड़े पैसे के लालच में अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराते थे। इसी के जरिए ठग धोखाधड़ी की रकम को वैध लेन-देन की तरह दिखाकर एक खाते से दूसरे खाते में खपाते थे। इस प्रक्रिया में खाताधारक स्वयं भी अपराध में सहभागी हो जाते थे।

कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम में उमड़ा उत्साह

■ आनंद कुमार और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने युवाओं को दिया सफलता का मंत्र

रायपुर/नवप्रदेश। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के पहल पर सरिया में आयोजित कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम में सुपरङ्क30 के संस्थापक पद्मश्री आनंद कुमार ने हजारों युवाओं को प्रेरणा से भर दिया। स्कूल मैदान में 3 हजार से अधिक युवा, शिक्षक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। पूरा मैदान युवाओं की तालियों और फ्लैशलाइट की रोशनी से गूंज उठा। मुख्य अतिथि आनंद कुमार ने छात्रों से कहा कि जीवन में बड़ा सपना देखें और उसे पूरा करने के लिए संकल्प और निरंतर मेहनत करें। उन्होंने कहा कि ÷जीवन में जितनी मुश्किलें आएंगी, सफलता उतनी बड़ी होगी। पढ़ाई मेहनत से होती है, पैसे से नहीं। शिक्षक नौकरी समझकर नहीं, बल्कि यज्ञ और जिम्मेदारी की भावना से पढ़ाएं। अपनी संघर्ष यात्रा बताते हुए उन्होंने कहा कि कैंब्रिज यूनिवर्सिटी में चयन होने के बाद भी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे नहीं जा पाए।

मासूम को अमानवीय सजा बिलासपुर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

■ हाई कोर्ट ने जताई चिंता, शिक्षा सचिव से मांगा शपथपत्र

बिलासपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से सोमवार को शिक्षकों का अमानवीय व्यव्हार सामने आया था। यहां के निजी स्कूल की शिक्षिकाओं ने बच्चे को सजा देते हुए पेड़ पर कपड़े के सहारे ही लटका दिया था। मामले में बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के डिवीजन बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे चिंताजनक बताया है। कोर्ट ने मामले में सख्ती दिखाते हुए शिक्षा सचिव से 9 दिसम्बर तक शपथपत्र मांगा है।

यह पूरा मामला हंस वाहिनी विद्या मंदिर नारायणपुर, आमापारा का है। जहां का एक वीडियो सामने आया है। जिसमें दिखाई दे रहा है कि, एक बच्चे को शिक्षकों ने पेड़ पर कपड़े के सहारे लटकाकर सजा दी है। बच्चा बेचारा उसी हालत में घूम रहा है। वहीं बच्चे को ऐसी सजा क्यों दी गई इसका कारण अब तक सामने नहीं आया है।

अभिभावकों में आक्रोश

वीडियो के वायरल होते ही अभिभावकों में भारी आक्रोश है। सभी ने मामले में संज्ञान लेकर प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग रखी है ताकि ऐसी घटना दोबारा दोहरे न जा सके। वहीं शिक्षा के मंदिर में ऐसी क्रूरता ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है।

स्कूल संचालक को यह सजा मामूली लग रही है उनका कहना है कि, बच्चा पढ़ता नहीं था और उसको डराने के लिए ऐसा किया गया है। बरहाल ऐसी तस्वीरें सामने आना कहीं ना कहीं विभाग के ऊपर भी कई सवाल खड़े करती है। ऐसे स्कूलों को जहां पर स्कूल संचालक करने की मूलभूत आवश्यकताओं के ना होते हुए भी मान्यता कैसे मिल जाती है। जांच के दौरान निजी स्कूलों में निम्न अनुसार मानकों में सही नहीं पाए जाने पर मान्यता रद्द कर दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के 32 निजी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश जारी किया है।

दोषियों के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही

वहीं कई बच्चों ने शिक्षक पर आरोप लगाते हुए कहा था कि, मैडम कुएं में लटका देती है। यह आरोप बेहद चिंताजनक है। वहीं घटना की वीडियो वायरल होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल शिक्षा विभाग के अधिकारी को मौके पर भेजा। फिलहाल विभाग की टीम मामले की जांच में जुट गई थी। उन्होंने बताया कि, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

होमवर्क पूरा न करने पर पेड़ पर लटकाया था

बालक नर्सरी क्लास में पढ़ाई करता है, उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। जिसके बाद शिक्षिकाओं ने रस्सी के सहारे सजा के तौर पर पेड़ में घण्टों तक लटका दिया। जिस वक्त बच्चे को पेट से लटकाया गया था किसी ग्रामीण ने इसका वीडियो बना सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा स्कूल पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर विरोध जताया।

न्यूज गैलरी

वीआईटी यूनिवर्सिटी मामले में जांच पैनल गठित, निजी विश्वविद्यालय रेगुलेटरी कमीशन ने आदेश जारी किए

भोपाल/नवप्रदेश। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय रेगुलेटरी कमीशन ने वीआईटी यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले की जांच के लिए विशेष पैनल का गठन किया है। आयोग ने तथ्यों की गहन पड़ताल कर रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। सीहोर की वीआईटी यूनिवर्सिटी में देर रात छात्रों ने खराब खाने को लेकर जमकर बवाल मचाया। इस मामले में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय रेगुलेटरी कमीशन ने तीन सदस्यीय जांच पैनल गठित किया है। पैनल से तीन दिन में जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है। आयोग द्वारा जारी आदेश में शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्यक महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अशोक शिवानी समिति की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा दो सदस्य शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय, भोपाल के प्राचार्य प्रो. संजय दीक्षित, शासकीय गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के प्राचार्य डॉ. लोकेंद्र दुबे बनाए गए हैं।

तीन दिनों में रिपोर्ट आयोग को सौंपनी होगी

समिति व्हीआईटी यूनिवर्सिटी में जाकर प्रबंधन, विद्यार्थियों और संबंधित पक्षों से चर्चा कर पूरे मामले की विस्तृत पड़ताल करेगी। जांच पूरी होने पर समिति को तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। बता दें वीआईटी यूनिवर्सिटी में 25 नवंबर की रात छात्रों ने प्रदर्शन और आगजनी की। बस में आग लगा दी और परिसर में जमकर तोड़फोड़ की। यह पूरा मामला यूनिवर्सिटी में खराब खाने को लेकर हुआ। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परिसर में शिक्षा के अनुकूल वातावरण बनाए रखना विश्वविद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी है और अनियमितता या लापरवाही पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

भोपाल में साइबर ठगों से घबराए एडवोकेट ने किया सुसाइड

अज्ञात कॉलर ने कहा था-दिल्ली ब्लास्ट में तुम्हारा नाम है, जल्द ही तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे

शिवकुमार वर्मा, मृतक

भोपाल/नवप्रदेश। भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में सोमवार को एक वरिष्ठ एडवोकेट ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा गया है कि किसी व्यक्ति ने फोन पर वकील को बताया था कि दिल्ली में हुई साजिश में तुम्हारा नाम आ गया है। अब जल्द ही तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनके शव का बुधवार को पोस्टमॉर्टम कराया गया। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जहांगीराबाद पुलिस के अनुसार 68 वर्षीय शिवकुमार वर्मा बरखेड़ी इलाके में रहते थे। वे वरिष्ठ एडवोकेट थे तथा वर्तमान में वकालत की प्रेक्टिस करते थे। मंगलवार रात करीब 7-30 बजे उन्होंने अपने घर में फांसी लगा ली। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया था जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा पंचनामा बनाकर जांच शुरू की।

सुसाइड नोट में क्या लिखा

पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है जिसमें वर्मा ने लिखा है कि पिछले दिनों उनके पास किसी अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया था। उसने कहा था कि तुम्हारा नाम हाल ही में दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके में आया है। जानकारी सामने आई है कि आतंकी साजिश में तुम्हारे बैंक खाते से फंडिंग की गई। यह फोन आने के बाद से वे तनाव में रहने लगे थे। पुलिस का अनुमान है कि आतंकी साजिश में फंसाने के नाम पर धमकी देकर उनसे ठगी की कोशिश की गई थी, लेकिन डर के कारण उन्होंने जान दे दी।

मप्र उर्दू अकादमी द्वारा साहित्य में अनुवाद परम्परा विषय पर आधारित सेमिनार एवं काव्यांजलि

भोपाल/नवप्रदेश। मध्यप्रदेश उर्दू अकादमी, मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद, संस्कृति विभाग के तत्त्वावधान में उर्दू एवं अन्य भाषाओं का अन्तर्सम्बन्ध के अंतर्गत ÷साहित्य में अनुवाद परम्परा÷ विषय पर आधारित सेमिनार एवं काव्यांजलि का आयोजन गुरुवार, 27 नवम्बर 2025 को शाम 5 बजे से महादेवी वर्मा हॉल, हिन्दी भवन, पॉलिटेक्निक चौराहा, भोपाल में किया जाएगा। उर्दू अकादमी की निदेशक डॉ नुसरत मेहदी ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम साहित्य में अनुवाद परम्परा पर आधारित है जिसमें प्रख्यात साहित्यकार डॉ. तकी आबिदी (कनाडा), इक़बाल मसूद (भोपाल)) दिनेश मालवीय (भोपाल) एवं स्तुति अग्रवाल (सिरोंज) अपने विचार व्यक्त करेंगे। इसके साथ ही काव्यांजलि के अंतर्गत विशेष प्रस्तुति के तहत मजाज आशना (बुरहानपुर) मेघदूत के काव्यात्मक उर्दू अनुवाद से चयनित अंश एवं हाशिम रजा जलालपुरी (रामपुर) कबीर और मीराबाई के काव्यात्मक उर्दू अनुवाद से चयनित अंश प्रस्तुत करेंगे।

प्रशिक्षित युवा विकसित और समृद्ध भारत का भविष्य बनेंगे : राज्यमंत्री टेटवाल

भोपाल/नवप्रदेश। कौशल विकास एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. गौतम टेटवाल आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि उन युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दे रहे हैं, जो आगे चलकर विकसित और समृद्ध भारत का भविष्य बनेंगे; इसलिए आपका आचरण, अनुशासन और कार्यशैली हर छात्र के लिए आदर्श होना चाहिए।÷ यह बात राज्य मंत्री डॉ. टेटवाल ने संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क, भोपाल में आयोजित कौशलम् समारोह में कही।

मंत्री श्री टेटवाल ने कहा कि कौशल प्रशिक्षण प्रदेश की आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण आधार है, और इसमें प्रशिक्षण अधिकारियों और प्राचार्यों की भूमिका अत्यंत निर्णायक है। उन्होंने कहा कि एक शिक्षक केवल पाठ पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि अपने संस्थान की संस्कृति, मूल्यों और अनुशासन का जीवंत प्रतिनिधि होता है। इसलिए शिक्षक का व्यवहार, भाषा, कार्यशैली और समय-प्रबंधन उस संस्था के स्तर को निर्धारित करता है। उन्होंने कहा कि आईटीआई का वास्तविक मूल्य उसके भवनों या मशीनों से नहीं, बल्कि वहाँ कार्यरत प्राचार्यों और प्रशिक्षण अधिकारियों से तय होता है। जब शिक्षक स्वयं आदर्श प्रस्तुत करते हैं, तभी विद्यार्थी उनमें वह प्रेरणा देख पाते हैं, जो उन्हें आगे बढ़ने और कुशल बनने की दिशा देती है। मंत्री डॉ. टेटवाल ने कहा कि शिक्षक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा, विनम्रता, दृढ़ता और कार्यनिष्ठा जैसी गुण होने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी इन्हीं गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं।

मंत्री श्री टेटवाल ने उद्योग जगत में हो रहे तेज बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि कौशल संस्थानों को नई तकनीकों, डिजिटल शिक्षण और व्यवहारिक प्रशिक्षण की दिशा में लगातार आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुसार प्रशिक्षण सामग्री और अभ्यास पद्धतियाँ विकसित करना अब समय की अनिवार्यता है। इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, लाइव प्रोजेक्ट और उद्योग यात्राएँ विद्यार्थियों को वास्तविक कार्यक्षेत्र से जोड़ने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं,

और इन्हें प्रत्येक संस्थान में और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए।उन्होंने बताया कि सरकार कौशल विकास संस्थानों के आधुनिकीकरण, उन्नत उपकरणों की उपलब्धता, डिजिटल संसाधनों के विस्तार और रोजगार केंद्रित प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर के कौशल प्रदान कर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अवसरों से जोड़ना विभाग की प्राथमिकताओं में शामिल है।

कौशलम् समारोह में इस वर्ष आईटीआई एवं कौशल विकास संचालनालय में चयनित प्राचार्य वर्ग-1, उपसंचालक, प्राचार्य वर्ग-2, सहायक संचालक और प्रशिक्षण अधिकारियों का उन्मुखिकरण किया गया। कार्यक्रम में उन प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर विभाग को नई पहचान दिलाई है। समारोह का उद्देश्य नई कार्यबल को प्रशिक्षण व्यवस्था, प्रशासनिक दायित्वों और उद्योग आधारित आवश्यकताओं की गहरी समझ देकर उन्हें प्रभावी भूमिका के लिए तैयार करना है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गिरीश शर्मा ने बताया कि वर्ष 2025 में आईटीआई प्रवेश में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। इस वर्ष पहली बार 52,248 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया संचालित की गई, जिसमें 49,402 सीटों पर प्रवेश हुआ, जो 94.55त्न है। महिला आरक्षण 30त्न से बढ़ाकर 35त्न किया गया, जिससे महिला प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 12,169 हो गई। प्रदेश के 10 प्रशिक्षणार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। आईटीआई की गुणवत्ता और आकर्षण को बढ़ाने के लिए 8वीं आधारित ट्रेड्स की संख्या बढ़ाई गई और आठ अन्य राज्यों से भी विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना और ह्वक्क के तहत हजारों अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

प्रदेश की 47 शासकीय आईटीआई ने 9 या अधिक ग्रेडिंग स्कोर प्राप्त किया, उज्जैन आईटीआई ने 9.30 स्कोर के साथ राष्ट्रीय स्तर पर 94वां स्थान प्राप्त किया। उद्योग एवं ष्टस्क्र साझेदारी के तहत आधुनिक लैब्स, ढ्ढ एवं इलेक्ट्रिकल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। अंतरराष्ट्रीय प्लेसमेंट और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जैसी उपलब्धियाँ प्रदेश के आईटीआई प्रशिक्षण की उत्कृष्टता को दर्शाती हैं। इन सभी उपलब्धियों के साथ आईटीआई केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि कौशल, रोजगार और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बनकर प्रदेश और देश के लिए गौरव का विषय बन गया है।

सागर मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड के श्री आशीष अग्रवाल ने बताया कि ओबैदुल्लागंज स्थित टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड प्लांट में सीखो कमाओ योजना के तहत 400 बच्चों का कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें से 60 बच्चों को सर्टिफिकेट दिए जा चुके हैं जिनका 100त्न प्लेसमेंट उनके प्लांट में हो गया है उन्होंने यह भी जानकारी दी की आईटीआई मंडीदीप ने उन्हें इस कार्य में हर संभव सहयोग दिया साथ ही मंशा जताई कि वह सरकार के सहयोग से इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने में के इच्छुक हैं।

मासूम से दरिंदगी, गांव में बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ा

रायसेन के पेरेंटेस बोले- डर लगता है बच्चों को कहीं कोई उठा न ले जाए

भोपाल/नवप्रदेश। मासूम से दरिंदगी के बाद गौहरगंज स्थित गांव में दहशत इस कदर फैल चुकी है कि गांव के बच्चों ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया है। आंगनबाड़ी से लेकर तीसरी कक्षा तक के छोटे-छोटे बच्चे पिछले तीन दिनों से स्कूल नहीं पहुंचे। इस कारण स्कूल में सन्नाटा पसरा है। ग्रामीण बताते हैं कि गांव के माहौल में भय व्याप्त है और पेरेंट्स, बच्चों को घर से बाहर भेजने तक से डर रहे हैं। एक महिला, जिनके दो बच्चे हैं, वह कहती हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चों को डर लगता है, वह कहते हैं कि उन्हें कहीं कोई उठा न ले जाए। तीन रोज से घर पर ही बैठे हैं। हम खुद भी स्कूल तक छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं।

इस तरह कई परिवारों की यही कहानी है। जिन घरों में कभी बच्चों की चहल-पहल रहती थी, वहां आज खामोशी छाई है। कई घरों में बच्चों ने बाहर खेलना तक बंद कर दिया है। पेरेंट्स लगातार बच्चों को अपने पास ही बैठाए रखते हैं। बता दें कि एम्स भोपाल के डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची की हालत स्थिर है और उसका इलाज चल रहा है।

आरोपी पर पहले से दो केस दर्ज

2024 में भोपाल के हनुमानगंज थाने में चोरी का एक मामला आरोपी आसिफ पर दर्ज है।

2019 में श्यामपुर में एक अन्य

चोरी का मामला आरोपी पर दर्ज है।

प्रिंसिपल बोलीं- अटेंडेंस 40प्रतिशत तक घटी

स्थानीय सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल ने बताया कि घटना के बाद स्कूल की अटेंडेंस 30: 40 प्रतिशत तक कम हो गई है। उन्होंने कहा आज हमने पेरेंट्स मीटिंग बुलाई थी। कई माताएं और कुछ पिता आए थे। सभी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। हम बच्चों और पेरेंट्स को आश्वस्त कर रहे हैं, लेकिन उनकी घबराहट वैसी की वैसी बनी हुई है। उन्होंने कहा कि स्टाफ लगातार बच्चों का मनोबल बढ़ाने और उन्हें मानसिक सुरक्षा देने की कोशिश कर रहा है। कुछ पेरेंट्स ने हमारी बात को समझा है तो अब जल्द ही बच्चे यहां वापस आएंगे। धरना स्थल पर माहौल उस समय और भावुक हो गया जब मासूम की नानी रोते हुए वे कपड़े लेकर बैठ गईं जिनमें बच्ची के साथ अपराध हुआ था। कपड़ों पर लगा खून देखकर वहां मौजूद महिलाएं और ग्रामीण खुद को रोने से रोक नहीं पाए। बार-बार कह रही थीं हमारी बच्ची को क्या हाल में छोड़कर गयाज ऐसा कभी नहीं देखा। हम आरोपी की फांसी या एनकाउंटर की मांग करते हैं। ग्रामीण कहते हैं कि यह घटना गांव की आत्मा को झकझोर देने वाली है।

चार दिन बाद भी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर

गांव और आसपास के क्षेत्रों में गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। आरोपी सलमान को घटना के चार दिन बाद भी पुलिस पकड़ नहीं सकी है। गांव की महिलाएं और युवतियां कड़ाके की ठंड में भी रातभर धरने पर बैठी हैं। उनका कहना है- अगर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही, तो एनकाउंटर कर दो, इतना तो इंसाफ मिलना चाहिए। स्थानीय निवासी परेश नागर ने बताया जब बच्ची को ओबेदुल्लागंज के सरकारी अस्पताल लाया गया, तो वह दो घंटे एम्बुलेंस के इंतजार में दर्द से तड़पती रही। बीएमओ ने फोन नहीं उठाया। अस्पताल में एक एम्बुलेंस खड़ी थी, लेकिन वह खराब थी। इतने बड़े क्षेत्र में व्यवस्था का यह हाल है। उन्होंने बताया कि एसडीएम मौके पर आ चुके थे, फिर भी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हुई। आखिरकार ग्रामीणों ने बच्ची को अपनी निजी कार से एम्स भोपाल पहुंचाया। परेश ने कड़े शब्दों में कहा- यह लापरवाही नहीं, अपराध है।

21 नवंबर की शाम बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी आरोपी सलमान उसे चॉकलेट दिलाने का लालच देकर जंगल की ओर ले गया। गांव के कई लोगों ने उसे बच्ची के साथ जाते देखा था। बच्ची बाद में जंगल में खून से लथपथ, दर्द से कराहती मिली। यह घटना ग्रामीणों को भीतर तक हिला गई है। परेश नागर ने बताया कि आरोपी श्यामपुर दौराहा क्षेत्र का रहने वाला है और वह जिला बदर रह चुका है। फिर भी वह गांव में किराए से रह रहा था। ऐसे अपराधियों की एंट्री पर निगरानी क्यों नहीं होती? पंचायत और पुलिस दोनों की बड़ी चूक है।

सांदीपनि विद्यालयों में आकांक्षी नामांकन की पूर्ति सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों से हो

स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किये निर्देश

भोपाल/नवप्रदेश। प्रदेश में नवीन भवनों में संचालित सांदीपनि विद्यालय में मॉडल अनुसार आकांक्षी नामांकन एवं वर्तमान नामांकन की रिक्तियों के आधार पर उनके आस-पास के शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों का प्रवेश कराये जाने के लिये जिला शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों को निर्देश दिये गये हैं। निर्देश में कहा गया है कि चयनित किये गये शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की सूची में से सामान्यत- प्राथमिक विद्यालयों को अधिकतम 2 किलोमीटर दूरी तक लिया जाये। कम नामांकन वाले विद्यालयों से शत-प्रतिशत प्रवेश सांदीपनि विद्यालयों में कराया जाए। निर्देशों में कहा गया है कि जिन निकटस्त शासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का प्रवेश शत-प्रतिशत सांदीपनि विद्यालयों में हो जायेगा, उन विद्यालयों को शिफ्ट करने का अनुरोध पोर्टल 3.0 पर अवश्य किया जाए। निर्देश में यह भी कहा गया है कि सांदीपनि विद्यालयों में प्रवेश के बाद शून्य नामांकन वाले विद्यालयों के शिक्षक यदि सांदीपनि विद्यालयों में अध्यापन के लिये सहमत होंगे, उन्हें वहीं रखा जायेगा। इसके बाद यदि कोई शिक्षक अन्यत्र जाना चाहते हैं, तो उन्हें कॉउंसलिंग से अन्य रिक्त पद वाले सरकारी विद्यालय में जाने का अवसर दिया जायेगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।

हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति

स्कूल शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक एवं अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति ई-अटेंडेंस के माध्यम से नियमित कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इस व्यवस्था की मॉनिटरिंग राज्य स्तर पर विभाग द्वारा समीक्षा के माध्यम से सुनिश्चित की जा रही है। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल तकनीक के ब?ते उपयोग से विद्यालयों में पठन-पाठन की प्रक्रिया में शिक्षकों के द्वारा डिजिटल डिवाइस जैसे- कम्प्यूटर, इंटरएक्टिव पेनल तथा टेबलेट का उपयोग किया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षकों की उपस्थिति को सटीक और सुगम तरीके से दर्ज करने के उद्देश्य से %हमारे शिक्षक ऐप% विकसित किया गया है। यह ऐप शिक्षकों की उपस्थिति की प्रक्रिया को ऑटोमेटेड, सुरक्षित और रियल टाइम बनाता है। शिक्षक अपने मोबाइल अथवा टेबलेट के माध्यम से ऐप में लॉगइन करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ऐप स्वत- लोकेशन, दिनांक, समय और फेस की पहचान को रिकॉर्ड करता है। इससे उपस्थिति वेरीफाइड हो जाती है। इसके अलावा लीव मैनेजमेंट शिक्षक ऐप के माध्यम से अवकाश के लिये आवेदन किया जा सकता है। संबंधित लीव का रिकॉर्ड ऑनलाइन रूप से

समृद्ध मप्र के लिये पंचायत प्रतिनिधि गांवों को बनायें समृद्ध : उपमुख्यमंत्री देवड़ा

स्वदेशी अर्थव्यवस्था में गांव में ही मिलेंगे रोजगार के अवसर

भोपाल/नवप्रदेश। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि गांव की समृद्धि ही मध्यप्रदेश की समृद्धि है। मध्यप्रदेश में विकास की गति को तेज बढ़ाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों को मिलकर अपने गांव को समृद्ध बनाना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के नेतृत्व में पंचायत प्रतिनिधियों को सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। श्री देवड़ा बुधवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभाग्रह में ÷आत्मनिर्भर पंचायत - समृद्ध मध्यप्रदेश÷ पर आयोजित राज्यस्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे।

उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि मध्यप्रदेश में अब ऐसे अवसर बन रहे हैं, जिससे गांव आत्म-निर्भर की ओर बढ़ रहे हैं। स्वदेशी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अब गांव में ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा। महिलाओं और युवाओं की विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी होगी। उन्होंने कहा कि पंचायत में वित्तीय पारदर्शिता की आवश्यकता है। इससे परस्पर विश्वास बढ़ता है और इसका लाभ विकास को आगे बढ़ाने में होता है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि

पंचायतें विकास की धुरी हैं। इसलिये उन्हें अपनी विकास योजनाएं बनाने की स्वतंत्रता दी गई है।

श्री देवड़ा ने पंचायत प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे विकास के कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध प्रयास करें। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विकास की ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं जो निचले स्तर तक विकास ला सकती है। उन्होंने कहा कि पंचायतों के पास वर्तमान में जितने अधिकार हैं उसका उपयोग कर पंचायतें विकास की गति में तेजी ला सकती हैं। श्री देवड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक देश को आर्थिक रूप से विश्व का समृद्ध देश बनाने का संकल्प लिया है। मध्यप्रदेश इस संकल्प को साकार करने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों को वित्तीय प्रबंधन व्यवस्थाओं में और ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। साथ ही महिला पंचायत प्रतिनिधियों और महिलाओं के स्व-सहायता समूहों को भी आगे आने की आवश्यकता है। कार्यशाला में त्रि-स्तरीय पंचायतों के प्रतिनिधि और पदाधिकारी उपस्थित थे।

सुविचार

सत्य को सब जानना चाहते हैं लेकिन जीना कोई नहीं चाहता क्योंकि जानना आसान है जीना मुश्किल। - अज्ञात

प्रवक्तओं की बद्जुबानी ने डुबोई नईया

बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के कारणों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस सहित उनके अन्य सहयोगी दल लगातार मंथन कर रहे हैं। यह बात अलग है कि वे महागठबंधन की पराजय के लिए एसआईआर और ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं लेकिन वे इस हकीकत से भली भांति परिचित हैं कि उनसे भी बड़ी चूक हुई है। जिसकी वजह से इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरह से महागठबंधन का सुपड़ा ही साफ हो गया है। तेजस्वी यादव ने तो विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन में बनाये गये और गाये गये गानों की पड़ताल भी शुरू करा दी है। गौरतलब है कि चुनाव प्रचार के दौरान राजद के समर्थन में जो गाने बजाए जा रहे थे उसमें कट्टा, दुपट्टा और रंगदारी जैसे आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया गया था। इस तरह के गानों ने भी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ मौहाल बनाया था अब तेजस्वी यादव ऐसे गानों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का मन बना रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की दो महिला प्रवक्ताओं ने भी राष्ट्रीय जनता दल की लुटिया डुबोने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। विभिन्न खबरिया चैनलों पर डिबेट के दौरान राजद की ये प्रवक्ता बद्तमीजी की सारी सीमाएं लांघ जाती थी। कोई भी पार्टी प्रवक्ता अपनी पार्टी का प्रतिबिंब होता है और उसे शालीनता से अपना पक्ष रखना होता है। वह भी तत्थों और तर्कों के साथ किन्तु राजद की ये दो प्रवक्तर सिर्फ बकवास करती थी यहां तक की गाली गलौज पर भी अमादा हो जाती थी। जिसकी वजह से अन्य पार्टी के प्रवक्ताओं और चैनलों के एंकरों के साथ भी उनकी बहस होती थी। इन दोनों प्रवक्ताओं के कारण भी बिहार के मतदाताओं तक यह संदेश पहुंचा था कि यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में फिर से जंगलराज वापस आ जाएगा। इसी तरह समाजवादी पार्टी में भी अनुराग भेदारिया और राजकुमार भाटी जैसे प्रवक्ता बहस कम और बकवास ज्यादा करते हैं। उनके कारण भी आने वाले उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अपने प्रवक्ताओं की बकलोली का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहरहाल बिहार में महागठबंधन की नैया डुबोने वाले प्रवक्ताओं को अब डिबेट में नहीं भेजा जा रहा है। यह महागठबंधन के हित में ही है कि वे बद्जुबान प्रवक्ताओं को टीवी डिबेट के बाहर ही रखे अन्यथा पार्टी की बची कूची साख पर भी बट्टा लग जाएगा।

ममता बनर्जी की गिदड़भभकी

बिहार के बाद चुनाव आयोग उत्तरप्रदेश और बंगाल सहित बारह राज्यों में एसआईआर करा रहा है जिसका बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार विरोध कर रही हैं। उन्होंने पहले तो निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी लेकिन जब उसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वे एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतर आई हैं। उन्होंने केन्द्र सरकार को गिदड़भभकी दी है कि यदि बंगाल में एसआईआर के नाम पर उनके समर्थकों के वोट काटे गये तो इसे वे खुद पर हमला मानेगी और पूरे देश को हिलाकर रख देंगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग ने एसआईआर के नाम पर बिहार में खेला कर दिया है लेकिन ये बिहार नहीं बंगाल है। यदि यहां ऐसी कोशिश की गई तो वे इसका जमकर विरोध करेंगी और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पूरे देश का दौरा करके भाजपा को खत्म कर देंगी। ममता बनर्जी की यह बौखलाहट इस बात का सबूत है कि बंगाल में लाखों की संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिये भरे पड़े हैं जिन्हें ममता बनर्जी की सरकार ने तमाम मूलभूत सुविधाएं मुहैया करा कर अपना वोट बैंक बना रखा है। इसका प्रमाण उस समय मिला जब एसआईआर के दौरान बंग्लादेश से लगे बंगाल के कई जिलों में वोटरों की संख्या में 65 प्रतिशत से भी ज्यादा का इजाफा देखने को मिला। जब इनकी पड़ताल होने लगी तो ये घुसपैठिए अपना घर बार छोड़कर वापस बांग्लादेश जाने के लिए बॉर्डर पर एकत्रित हो गये हैं और उनमें से कई बंग्लादेश पहुंच भी गए हैं। ममता दीदी को अपना वोट बैंक दरकता नजर आ रहा है और इसीलिए उन्होंने चुनाव और केन्द्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है और अब वे धमकी चमकी पर उतर आई हैं लेकिन एसआईआर का काम तो हर हाल में होगा सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर के काम में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। बेहतर होगा कि ममता बनर्जी इस तरह की धमकी देना बंद करें और एसआईआर के काम में सहयोग दें।

सदगुरू बोधामृतम

सदगुरू ऋतेश्वर जी

❖ परमात्मा का सबसे पसंदीदा चीज है सर्शष्ट का विस्तार। ठाकुर जी को सबसे अच्छा लगता है सर्शष्ट विस्तारित हो इसलिए स्त्री-पुरुष का निर्माण किया पर अपनी मूल सहज स्वरूप में स्त्री-पुरुष हो तब वो सर्शष्ट संगीत की लहरी बनती है और अपने मूल प्रकृति से अलग हो गए हो तब वो डिजास्टर बन जाता है, आपदा बन जाती हैं। वस्तु का उपभोग करना बुरा नहीं है, वस्तु में सुख का कारण है ये मान लेना तुम्हारे दुर्भाग्य का कारण है।

आज का इतिहास

नई दिल्ली(वार्ता)। 1815 पोलैंड साम्राज्य ने संविधान अपनाया। 1838 पेस्ट्री युद्ध में फ्रैंक बलों द्वारा मेक्सिको पर आक्रमण किया गया। 1888 अंतर्राष्ट्रीय डेल्टा डेल्टा डेल्टा सोरोरिटी की स्थापना बोस्टन विश्वविद्यालय में की गयी। 1889 क्लेमसन विश्वविद्यालय दक्षिणी कैरोलिना में स्थापित किया गया। 1905 जापान और कोरिया ने ईलासा संधि पर हस्ताक्षर किये। 1912 अल्बानिया ने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। 1953 अमरीका के विख्यात ड्रामा लेखक पूजीन ओ नील का 65 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 1966 उरुग्वे ने संविधान अपनाया। 1971 सोवियत रूस के 'मार्स ऑर्बिटर' द्वारा मंगल ग्रह पर उतारा गया।1978 कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, जो एक स्वायत्त कुर्द राज्य के गठन पर तुर्की के साथ संघर्ष में थी, की स्थापना की गई थी। 1978 सैन फ्रांसिस्को के मेयर जॉर्ज मॉस्कॉन और खुले तौर पर समलैंगिक पर्यवेक्षक हार्वे मिल्क की हत्या सुपरवाइजर डैन व्हाइट ने की थी।

श्रमेव जयते! आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधार

डॉ. मनसुख मांडविया
केंद्रीय श्रम रोजगार एवं खेल मंत्री

वे निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देती हैं और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करती हैं। ये संहिताएं ऑडियो-विजुअल श्रमिकों और गिग तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों को औपचारिक मान्यता प्रदान करती हैं। ये अखिल भारतीय ईएसआईसी कवरेज को सक्षम बनाती हैं, 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य करती हैं, जिनमें पहले बाहर रखे गए बागान श्रमिक भी शामिल हैं। साथ ही, ये राज्यों में असमानताओं को कम करने के लिए सभी श्रमिकों के लिए वैधानिक न्यूनतम वेतन की गारंटी देती हैं। अनिवार्य नियुक्ति पत्र, पक्की पे स्लिप और सवेतन वार्षिक अवकाश जैसे प्रावधान हर श्रमिक को अधिक स्थिरता, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आधारित रोज़गार के एक प्रगतिशील विकल्प के रूप में, संहिताओं में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी निश्चित अवधि के रोजगार की शुरुआत की गई है।

कई दशकों तक भारत कमज़ोर आर्थिक विकास, गहरे भ्रष्टाचार और रोज़गार सृजन व श्रमिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के अभाव से जूझता रहा। राजनीतिक उद्देश्यों से होने वाले घेराव और बंदी ने बार-बार औद्योगिक गतिविधियों को बाधित किया, निवेश को रोका और व्यवस्था में विश्वास को कम किया। यह दुख की बात है कि पिछली सरकारों ने श्रमिक कल्याण को केवल नारों तक सीमित कर दिया और श्रमिकों के वास्तविक मुद्दों को गंभीरता से लेने में विफल रहीं।

इस जड़ता को तोड़ने के लिए देश के नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव जरूरी था। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'श्रमेव जयते' का आह्वान किया और कहा कि भारत की विकास यात्रा के केंद्र में श्रम की गरिमा यानी मजदूरों का सम्मान होना चाहिए।

यह केवल एक नारा नहीं था, बल्कि एक नई राष्ट्रीय सोच की शुरुआत थी, जिसमें नीतियां बनाते समय श्रमिकों को केंद्र में रखा गया। ऐसे बदलाव की जरूरत बहुत समय से महसूस की जा रही थी। भारत के ज़्यादातर श्रम कानून 1920 से 1950 के बीच बने थे और उनमें औपनिवेशिक सोच की झलक रहती थी। दूसरी ओर, दुनिया में काम करने का तरीका पूरी तरह बदल चुका था। गिग और प्लेटफ़ॉर्म अर्थव्यवस्था का बढ़ना, डिजिटल कामकाज, लचीली कार्य संरचनाएं और नए प्रकार के उद्यम तेजी से उभर रहे थे। लेकिन भारत के पुराने श्रम कानून समय के साथ नहीं बदले, और आधुनिक कार्यबल या प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे थे। एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पंच प्रण के माध्यम से यह संदेश दिया कि हमें औपनिवेशिक मानसिकता छोड़कर भविष्य की जरूरतों के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। पुराने कानून इसलिए नहीं बने रहे क्योंकि वे अच्छे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि पिछली सरकारों में उन्हें बदलने का राजनीतिक साहस, इच्छा शक्ति और दूरदृष्टि की कमी थी। बदलती परिस्थितियों और देश की जरूरतों के अनुसार उन्हें आधुनिक बनाने की हिम्मत किसी ने नहीं दिखाई।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भारत का वैश्विक कद अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। दुनिया मानती है कि भारत अब भविष्य को आकार देने में केवल भाग नहीं ले रहा है, बल्कि उसे परिभाषित करने में भी मदद कर रहा है। लेकिन इस ऐतिहासिक क्षण का सही अर्थों में लाभ उठाने और संभावनाओं को दीर्घकालिक समृद्धि में बदलने के लिए, भारत

औपनिवेशिक काल के उस श्रम ढांचे से बंधा नहीं रह सकता जो सशक्तिकरण के बजाय नियंत्रण के लिए बनाया गया था।

इसलिए, बड़े पैमाने पर रोज़गार सृजन, औपचारिकता का विस्तार और सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक बदलाव आवश्यक था। इस राष्ट्रीय आवश्यकता को समझते हुए, मोदी सरकार ने स्वतंत्र भारत के सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक को लागू किया। पहले के 29 बिखरे हुए श्रम कानूनों को मिलाकर चार सरल और स्पष्ट श्रम संहिताएं बनाई गईं : वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता।

21 नवंबर 2025 को ये श्रम संहिताएं लागू हो गईं। ये संहिताएं मिलकर एक आधुनिक श्रम ढांचा स्थापित करती हैं, जो श्रमिक-समर्थक और विकास-समर्थक दोनों है, और यह दिखाता है कि भारत अब तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है।

संसद द्वारा 2019 और 2020 में श्रम संहिताओं को पारित किया गया था, कई राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, श्रमिक संघों और उद्योग निकायों ने उनके प्रगतिशील इरादे का स्वागत किया है। उनकी खूबियों को पहचानते हुए, सभी राजनीतिक दलों के राज्यों ने संहिताओं के अनुसार से अपने श्रम कानूनों में बदलाव किए। उदाहरण के लिए, जिन राज्यों ने महिलाओं को उनकी सहमति और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात में काम करने की अनुमति दी है, वहाँ कुल महिला रोजगार में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

सभी क्षेत्रों के स्टेकहोल्डर्स ने एक पुरानी हो चुकी श्रम प्रणाली से आगे बढ़ने की आवश्यकता को पहचाना है। उनके योगदान ने एक संतुलित ढाँचा तैयार करने में मदद की है जो श्रमिकों की सुरक्षा करता है और साथ ही अर्थव्यवस्था को विकसित होने में भी सक्षम बनाता है।

श्रमिकों और इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मेरी बातचीत में जो बात हमेशा सामने आई है वह कार्यस्थल पर स्पष्टता, निष्पक्षता और सम्मान की आवश्यकता पर बल देती है। इसी मार्गदर्शक सिद्धांत ने हमारे सुधारों को आकार दिया है, जिसने एक जटिल और बिखरे हुए सिस्टम को एक ऐसे सिस्टम से बदल दिया है जो सरल, पारदर्शी और हर श्रमिक की सुरक्षा करने वाला है। श्रम संहिताएं अपने मूलभाव और अक्षरशः रूप में, नियोक्ताओं की अपेक्षाओं को संतुलित करते हुए श्रमिकों के हितों को प्राथमिकता देती हैं। वे निवारक स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देती हैं और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करती हैं।

ये संहिताएं ऑडियो-विजुअल श्रमिकों और गिग तथा प्लेटफॉर्म श्रमिकों को औपचारिक मान्यता प्रदान करती हैं। ये अखिल भारतीय ईएसआईसी कवरेज को सक्षम बनाती हैं, 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य करती हैं, जिनमें पहले बाहर रखे गए बागान श्रमिक भी शामिल हैं। साथ ही, ये राज्यों में असमानताओं को कम करने के लिए सभी श्रमिकों के लिए वैधानिक न्यूनतम वेतन की गारंटी देती हैं। अनिवार्य नियुक्ति पत्र, पक्की पे स्लिप और सवेतन वार्षिक अवकाश जैसे प्रावधान हर श्रमिक को अधिक स्थिरता, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आधारित रोज़गार के एक प्रगतिशील विकल्प के रूप में, संहिताओं में फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी निश्चित अवधि के रोजगार की शुरुआत की गई है।

एक राष्ट्रीय संकल्पः संपूर्ण सरकार और समाज साझा रूप से बाल विवाह मुक्त भारत की ओर अग्रसर

- अन्नपूर्णा देवी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री

एक ऐसे देश में जहाँ महिलाएँ और बच्चे एक अरब से ज़्यादा जीवनों का आधार हैं, उनका सशक्तिकरण महज़ एक नीतिगत विकल्प नहीं है, बल्कि यह भारत की नियति का मार्ग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी शासन में, भारत एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुज़र रहा है, जो वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को मानव-केंद्रित प्रगति के साथ जोड़ रहा है। नए भारत की कहानी केवल आर्थिक उपलब्धियों और बढ़ते वैश्विक कद में ही नहीं, बल्कि उन कक्षाओं में भी आकार ले रही है, जहाँ युवा मन विकसित होते हैं, उन आंगनवाड़ी केंद्रों में जहाँ हमारे बच्चों का पालन-पोषण होता है, और उन घरों में जहाँ आकांक्षाएँ पनपती हैं।

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के प्रति प्रधानमंत्री की अटूट प्रतिबद्धता, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति बन गई है, जो विकसित भारतञ्च2047 के लिए हमारे सामूहिक मिशन को भी आगे बढ़ा रही है। इसी सफर में एक अहम पड़ाव पिछले वर्ष 27 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ है।

अपनी साहसिक और अटल दृष्टि के साथ, हमने वर्ष 2030 तक बाल विवाह को खत्म करने की अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराई है, ताकि हर बालिका और बालक सुरक्षित रूप से बड़े हो सकें, अपनी शिक्षा जारी रख सकें और गर्व तथा आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य को आकार दे सकें। शुरू से ही, हमने 'संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज' के नज़रिए को अपनाया है, लिहाज़ा हम मानते हैं कि इस चुनौती का हल महज़ नीतियों से नहीं किया जा सकता। इसके लिए सामूहिक एकता की ज़रुरत है, जिसमें परिवार, समुदाय, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, संस्थान और सरकार कंधे से कंधा मिलाकर, सदियों पुरानी प्रथा को तोड़ने और हर बच्चे की आकांक्षाओं की रक्षा करने के लिए एक साथ खड़े हों। हमारे साझा संकल्प के एक शक्तिशाली प्रतिबिंब के रूप में, गाँवों और कस्बों के करोड़ों लोग बाल विवाह को समाप्त करने का संकल्प लेने के लिए आगे भी आए हैं।

बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 'पूरी सरकार' एकजुट

बाल विवाह हमारे देश में पीढ़ियों से चली आ रही सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह अक्सर उन समुदायों में दिखती है, जहाँ शिक्षा, संसाधनों और जागरूकता की सीमित पहुँच है। अभाव और असमान अवसरों के कारण पैदा हुई ये कमियाँ, इस प्रथा को जारी रखने में मदद करती हैं, जिससे अनगिनत बच्चे अपने उज्ज्वल भविष्य को साकार करने से वंचित रह जाते हैं।

वर्तमान में बेहतरी के लिए प्रयासः मोदी सरकार के तहत, हम उन जड़ों को खत्म कर रहे हैं, जिन्होंने कभी इस प्रथा को पोषित किया था। स्पष्ट नीतिगत दिशा, विचार विमर्श कर तैयार की गई योजनाओं और शासन में समुदायों के नए विश्वास के साथ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उन परिस्थितियों को खत्म करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिनके कारण बाल विवाह की प्रथा अब तक जारी रही। आज हम जो प्रगति देख रहे हैं, वह सुनियोजित ढंग से तैयार की गई योजनाओं की वजह से हैं, जिनके तहत महिलाएं और बच्चे राष्ट्रीय विकास के केंद्र में हैं।

हमारी नीतियां और पहल, संवेदनशील कारणों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर अधिकार, देश के सबसे दूरस्थ गाँव और बस्तियों में सबसे कमजोर बच्चे के जीवन पर सकारात्मक असर डालते हुए अंतिम छोर तक पहुँचे। सरकार की हर योजना महिलाओं और बच्चों को जोखिम के हर चरण में सहारा देने के लिए तैयार की गई है, ताकि अजन्मे बच्चे से लेकर किशोरी तक, उनके जीवन के हर चरण की सुरक्षा, प्राथमिकता और सशक्तिकरण हो।

पोषण ट्रैकर और पोषण भी पढ़ाई भी से लेकर समग्र शिक्षा अभियान तक, और राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति कार्यक्रम से लेकर प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना तक, हर पहल एक सुरक्षा कवच और हर बच्चे के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान भविष्य की ओर एक मार्ग के रूप में कार्य करती है।

समावेशन के उत्प्रेरक के रूप में तकनीक की मदद से, मंत्रालय का प्रमुख डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, पोषण ट्रैकर, 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को स्तनपान कराने वाली माताओं, छह साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरियों से सहजता से जोड़ता है। इसने देश भर में 10.14 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए एक मज़बूत सुरक्षा तंत्र तैयार कर दिया है। इस डिजिटल सक्षमता के साथ पोषण भी पढ़ाई भी, एक बदलावकारी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पहल के रूप में तैयार हुआ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पूर्व-प्राथमिक बच्चे को समग्र, उच्च-गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक प्रोत्साहन मिले, जो आजीवन सीखने की भावना की नींव रखता है।

हमारी नीतियाँ न केवल इरादे, बल्कि ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई को भी दर्शाती हैं। निरंतर बजटीय प्रतिबद्धताओं और लक्षित निवेशों में सुधारों को शामिल करते हुए, मोदी सरकार ने यह साफकर दिया है कि बाल विवाह जैसी गंभीर समस्याओं से बच्चों की रक्षा करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी हुई है। राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति कार्यक्रम, जिसके लिए केवल 2025-26 के लिए 1,827 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण स्कूल न छोड़े, जो बाल विवाह के सबसे अहम कारणों में से एक है। इस बीच, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली युवतियों को ज़रुरी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

पाठकों की बात | पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

बिंदास अंदाज़

बिंदास अंदाज़ मैं जीते जाना है... आये कोई तूफ़ान बस बढ़ते जाना है... गिराते है लोग उन्हीं को जिसमें चलने का हौसला मुझे तो हर कदम पर यूँ ही सम्भलते जाना है... छू लूँगी आसमां मैं भी बस एक दिन.... ईमान के लहजे से दिखना और एहसासों के साथ अपने अंदाज में निखरते जाना है... कि हूबहू आईने में कभी समय से मिले भी ना मेरी शक्ल मगर मेरी रुह के अंदाज़ से लोगो ने मुझे पहचाना हैं...और मुझे बस चलते जाना है...!!

- नंदिता तनूजा

छेड़ दी तान फिर

छेड़ दी तान फिर इक नयी क्या करें खल्क में मच गई खलबली क्या करें ढल गयी रात इक महकते ख्वाब में बात सब रह गयी अनकही क्या करें दिल लगाया बहुत शायरी में मगर सब्र की हर लहर छल गयी क्या करें शब चुरा ले गयी चांद - तारें कहीं हर सुबह कर गई दिल्लगी क्या करें ना मिला ज़ीस्त की रहगुज़र का पता छान डाली मगर हर गली क्या करें।

- रामकिशोर उपाध्याय

पोथी पढ़-पढ़ रट्टू होगें फेर सत् के

पोथी पढ़-पढ़ रट्टू होगें फेर सत् के पहिचान नहीं काला कहिथें गरब के रद्दा तेकरो बिल्कुल ज्ञान नहीं बस लकीर के फक्रीर बनगे हें देख कथित विद्वान मन तब सत-अंजोर कइसे पावयँ इँकर भरोसा आम-जन। **- सुशील भोले**

अजब सी बेक़रारी हो गई

अजब सी बेक़रारी हो गई है। मुहब्बत दिल पे तारी हो गई है ।। ज़रा से आप क्या नज़दीक आए। ग़ज़ब हालत हमारी हो गई है।। न जीते हैं, न मरते हैं वफ़ा में। तबीयत भारी भारी हो गई है।। तुम्हें जिस दिन से देखा क़सम से। पिए बिन ही ख़ुमारी हो गई है।। मुहब्बत हो गई संजय तुम्हें भी। ये सबको जानकारी हो गई है।। **- संजय कुमार गिरि**

खुले बंधन सधे चितवन अडिग संकल्प

खुले बंधन सधे चितवन अडिग संकल्प दृढ़ मन में धरा होगी मेरी अपनी खुलेंगें पँख गगन-वंदन में !! पल्लवित पुष्प डारी-डारी कूकती कोकिला उपवन में बस रहा राग मधुर निर्झर मुक्त-हृदय के कण-कण

में !! चिरैया उड़ चली ले कर अटल विश्वास अनंत मन में दीप्त होंगी अभिलाषा भरे जो स्वप्न हैं नभ-नयन में!!

- अंजू डोकानिया

कुछ लोग मिलते हैं और ज़िंदगी

"कुछ लोग मिलते हैं और ज़िंदगी में रंग भर देते हैं। दूर होकर भी यादों की महक छोड़ जाते हैं।" लोग भी फूलों जैसे होते हैं कुछ लोग रंग बन जाते हैं! महकते हैंज याद बनकर! फूल भीज और लोग भी! जो मिलें तो रंगज बिछड़ें तो महक! **- रेनु सिंघल**

जब भी मैं देखता हूँ, मुस्कुराती

जब भी मैं देखता हूँ, मुस्कुराती हुई अपनी तस्वीर को तब-तब वह मुझसे कहती है- "तुम जो मुझमें मुस्कुरा रहे हो ना वह तुम्हारी असली मुस्कान नहीं है बनावटी है खोखली है तुम मेरे द्वारा दूसरों को यह जताने की कोशिश में लगे हो कि मैं बहुत खुश हूँ" और ऐसा कहते हुए मेरी बनावटी मुस्कान के पीछे हँसती है और मुझे मुँह चिढ़ाने लगती है मेरी तस्वीर। **- भाऊराव महंत**

राशि फल

पं. देवव्रत शर्मा

मेष : आज आपकी कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ेगी, जिससे आपको बिजनेस को एक नई राह में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

वृषः आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है। आपको अपने किसी लेनदेन से संबंधित मामले पर पूरा ध्यान देना होगा।

मिथुनः आज आपके कोई मन की इच्छा पूरी होने से खुशी होगी। यदि किसी काम को लेकर आप लंबे समय से परेशान थे, तो वह पूरा हो सकता है।

कर्कः आज आप अपने खर्चो को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके मनमौजी स्वभाव के कारण आपके खर्चे बढ़ेंगे।

सिंहः आज का दिन आपके लिए समस्याओं से भरा रहने वाला है। आज आपका मन काम को लेकर परेशान रहेगा।

कन्याः आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। आपकी नौकरी में अपने बॉस से यदि किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी।

तुलाः आज का दिन आपके लिए मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी।

वृश्चिकः आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपको धैर्य और साहस से काम लेने की आवश्यकता है।

धनुः आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। भगवान की भक्ति में आपका खूब मन लगेगा।

मकरः आज का दिन राजनीति में कार्यरत लोगों के लिए बढ़िया रहने वाला है। आपकी अपने किसी परिजन से लंबे समय बाद मुलाकात होगी।

कुंभः आज का दिन आपके लिए उन्नति की राह में आगे बढ़ने के लिए रहेगा।

मीनः आज आप परोपकार के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और आप परिवार के सदस्यों के साथ आनंदमय समय व्यतीत करेंगे।

सूर्योदय : 06:48, सूर्यास्त : 17:40, चन्द्रोदयः 9 11:36, चन्द्रास्तः 9 22:48, अयन : दक्षिणायन, ऋतु : हेमन्त, शक सम्वत : 1947 (विश्वावसु), विक्रम सम्वत : 2082 (सिद्धार्थी), युगाब्द (कलि संवत) 9 5127, मास : मार्गशीर्ष, पक्ष : शुक्ल तिथि : षष्ठी (22:56 से सप्तमी), नक्षत्र : धनिष्ठा, योग : ध्रुव, प्रथम करण : कौलव (11:33 तक), द्वितीय करण : तैतिल (24:01+ तक)

॥ गोचर ग्रहः ॥

सूर्य : वृश्चिक, चंद्र : मकर, मंगल : वृश्चिक (अस्त, पूर्व, मार्गी), बुध : तुला (अस्त, पश्चिम, वक्री), गुरु : कर्क (उदित, पश्चिम, वक्री), शुक्र : वृश्चिक (उदित, पूर्व, मार्गी), शनि : मीन (उदित, पश्चिम, वक्री), राहु : कुम्भ, केतु : सिंह।

QUIZ TIME

Ramaquiz

1) तंबाकू उद्योग में भारत का स्थान क्या है?

2) डेजर्ट नाइट नामक त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया?

3) प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश में नव घोषित जिले का नाम क्या है?

4) हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों का सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया?

5) रुशिकोंडा बीच, जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है?

उत्तरमाला- (1) दूसरा (2) भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात (3) महाकुंभ मेला (4) कोलंबो, श्रीलंका (5) आंध्र प्रदेश

कार्टून

शब्द सामर्थ्य -240 (भागवत साहू)

बाएं से दाएं
1. बात, घटना, गाजरा, युक्तदगा (ठर्द) 3. अलावा, अतिरिक्त 6. प्रेम, इच्छा 7. मां का बच्चे के प्रति प्रेग 8. गलती, जुर्म, गुनाह, दोष 10. मान, लीन, खुश, प्रसन्न 12. भतुष, समादेश, फौजी टुकड़ी 13. एक काल्पत पत्थर जो लोहे को छूकर सोना बना देता है 16. हिम्मत, साहस, सामर्थ्य 17. बनावटी, अनुकृति, असली का विलोम 18. अबोध, नासमझ 20. ब्रह्मपुत्र एक प्रसिद्ध हरिभक्त देवर्षि 22. गहरा नीला, काला 23. व्याकुल, बेसब्र 24. गन, चित, आदरसूचक तथा सहमति सूचक एक शब्द।

ऊपर से नीचे
1. रचागी, नाथ 2. बेचैन, गजबूर, विवश 3. आन्नाम, अत्याचार, जुल्म 4. मध्य एशिया का एक देश 5. पुस्तक 9. बहादुर, वीर 11. सैनिक विद्रोह 12. नीच, अधम 12 प, प्रणाम, झुकना 13. भरण पोषण करना, परवरिश करना, छोटा झूला, हिंडोला 14. प्रमाण, प्रमाणिक कथन 15. स्वाभाविक ढंक, योग्यता, लियाकत, सभ्यता और शिष्टता, शकर (उ.) 19. बिजली, तड़ित 21. रात में दिखाई न पड़ने का नेत्र संबंधी रोग।

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 239 का हल

प	सं	द		सिं	हा	स	न	
ख		म	ज	दू	र		का	म
बा	द	क		र		सं	ब	ल
ड़		ल	ज्जा		म	स्का		य
	बा			बि	हा	र		
सु	धा	क	र		न			औ
रं		म		कि	ता	ब		स
ग		अ	र	सा		हु	ज्ज	त
	श	क्ल		न	मि	त		न

लक्ष्य बड़े रखें, उत्साह से कार्य करने पर निश्चित रूप से मिलेगी सफलता : उप मुख्यमंत्री देवड़ा

उप मुख्यमंत्री ने जेंडर कैंपेन नई चेतना 4.0 का किया शुभारंभ

पंचायतों में बिना मांग स्वीकृत किए नए भवन, अब तीन मंजिल तक कर सकेंगे निर्माण- मंत्री पटेल

पंचायत प्रतिनिधियों एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की तीन दिवसीय कार्यशाला का समापन

भोपाल/नवप्रदेश। पंचायतों को आत्मनिर्भर, सशक्त एवं समृद्ध बनाने के लिए कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 24 नवंबर से चल रही पंचायत प्रतिनिधियों एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारियों की तीन दिवसीय कार्यशाला का बुधवार को समापन हो गया। कार्यशाला के अंतिम दिन उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने जिला पंचायत सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने मध्यप्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित जेंडर कैंपेन नई चेतना 4.0 का शुभारंभ किया। उत्कृष्ट लोक अधिकार केंद्रों के माध्यम से महिलाओं के हक एवं अधिकारों पर कार्य करने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। मन में काम करने का उत्साह रहेगा तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। उन्होंने कार्यशाला में मौजूद जन-प्रतिनिधियों से सरकार की योजनाओं को आगे बड़ाने की अपील की।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि इस बार कार्यशाला में सरपंच संगठन, सचिव संगठन और जीआरएस संगठन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा की जनप्रतिनिधियों को अधिकारों और कर्तव्यों पर गंभीरता से विचार कर सार्वजनिक जीवन में बनी नकारात्मक धारणा को समाप्ड़त करते हुए पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जहां पंचायत भवन नहीं थे, वहां बिना मांग के नए भवन स्वीकृत किए गए। अब पंचायत भवन तीन मंजिला बनाए जाएंगे, जिससे भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार उनका उपयोग हो सकेगा। इसी तरह ग्राम पंचायत, जनपद पंचायतों में सामुदायिक भवन भी बनवाए जा रहे हैं। पंचायतों को ग्राम सुरक्षा, स्वच्छता और सामाजिक उत्तरदायित्व के विषयों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि को स्वयं से तीन प्रश्न जरूर पूछने चाहिए। पहला- मेरे कर्तव्य क्या हैं दूसरा- मेरा वित्तीय प्रबंधन कितना पारदर्शी है? और तीसरा- समाज के लिए मेरा योगदान क्या है। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य और ईमानदारी पर अडिग रहना ही जनसेवा का मूल सिद्धांत है।

कार्यशाला के आखिरी दिन दो सत्र हुए। इसमें प्रदेश के जिला पंचायत सदस्य शामिल हुए। जिला पंचायत की स्थायी समितियों की नियमित बैठकें एवं जिला पंचायत डेवलपमेंट प्लान को लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने बेहतर विकास को लेकर सुझाव दिए। बैठक में क्षेत्र के विकास को लेकर भी चर्चा हुई। कार्यशाला में पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह, संचालक श्री छोटे सिंह, एसआरएलएम की सीईओ श्रीमती हर्षिका सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

एसआईआर पर बवाल, आज चुनाव आयोग का घेराव करेगी युवा कांग्रेस

विपक्षी मतदाताओं को सूची से हटाने का आरोप

भोपाल/नवप्रदेश। 27 नवंबर को युवा कांग्रेस राजधानी भोपाल में चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करने जा रही है। संगठन का दावा है कि भाजपा एसआईआर प्रक्रिया को वोट चोरी का हथियार बनाकर लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला कर रही है, और अब इस अन्याय के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। मध्यप्रदेश में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (स्ढ्ढक्र) को लेकर बड़ा राजनीतिक घमासान खड़ा हो गया है। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एसआईआर प्रक्रिया के नाम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए टारगेटेड डिलीशन करा रही है यानी खास वर्गों और विपक्षी गढ़ों में हजारों मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। इसी विरोध में युवा कांग्रेस ने 27 नवंबर को चुनाव आयोग कार्यालय का विशाल घेराव करने की घोषणा की है। युवा कांग्रेस का दावा है कि प्रदेशभर से हजारों कार्यकर्ता भोपाल में प्रदर्शन करेंगे, जिसमें एसआईआर की प्रक्रिया को अवैध, पक्षपातपूर्ण और लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा जाएगा।प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मध्यप्रदेश प्रभारी शिविसिंह चौहान ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज चुनाव आयोग भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहा है। मतदाता सूची से नाम हटाने की कार्रवाई लक्षित तरीके से हो रही है। आयोग अपनी निष्पक्षता खो चुका है और एक राजनीतिक दल की छाया बन गया है। चौहान ने आरोप लगाया कि कई विधानसभा क्षेत्रों में बिना सूचना दिए हजारों वास्तविक मतदाताओं के नाम काट दिए गए। उन्होंने यह भी दावा किया कि जब शिकायत दर्ज कराई जाती है, तब भी सुधार नहीं होता। मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस के नव-निर्वाचित अध्यक्ष यश लखन घनघोरिया ने कहा कि एसआईआर को चुनावी हथकंडा बनाकर भाजपा विपक्षी मतदाताओं को सूची से हटाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमने कई क्षेत्रों में पाया है कि बूथ-स्तर पर भाजपा से जुड़े लोग मतदाता सत्यापन की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहे हैं। वे उन घरों को 'अनुपस्थित' दिखा रहे हैं जहां लोग मौजूद हैं। यह साफ-साफ वोट चोरी का प्रयास है।घनघोरिया ने घोषणा की 27 नवंबर को भोपाल में ऐतिहासिक घेराव होगा। हजारों युवा साथी यह संदेश देंगे कि लोकतंत्र की हेरफेर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी।उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस आगे भी हर जनविरोधी निर्णय का खुलकर विरोध करेगी। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय सचिव और सह-प्रभारी रूपेश सिंह भदौरिया ने भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा मैदान में चुनाव जीत नहीं पा रही, इसलिए एसआईआर की आड़ में मतदाताओं के अधिकार छीनने की रणनीति बना रही है। यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर हमला है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एसआईआर की खामियों को दूर नहीं किया गया तो युवा कांग्रेस जिला-स्तर पर भी व्यापक आंदोलन छेड़ेगी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मितेन्द्र दर्शन सिंह यादव ने कहा कि संगठन बूथ-स्तर पर सत्यापन कर रहा है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर जहां भाजपा कमजोर है, वहां हजारों असली मतदाताओं को डिलीट कर दिया गया है। वहीं भाजपा से जुड़े कुछ इलाकों में फर्जी और गैर-मौजूद लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। हम हर ऐसे प्रयास का पूरी ताकत से पर्दाफाश करेंगे। यादव ने दावा किया कि युवा कांग्रेस मतदाता सूची में पारदर्शिता बहाल करने के

पारिवारिक दायित्वों, व्यक्तिगत चुनौतियों को भी नजर अंदाज़ कर राष्ट्र हित में एसआईआर किया शतप्रतिशत

भोपाल/नवप्रदेश। नर्मदापुरम जिले की विधानसभा 139: पिपरिया के मतदान केंद्र 176 बो?नाठाकुर के बीएलओ श्री विष्णु पाटर ने स्ढ्ढक्रके कार्य को अपने निजी और पारिवारिक कार्य पर प्राथमिकता देते हुए दिनांक 24 नवम्बर को अपने पुत्र के विवाह के दिन की रस्मों को संपन्न कर रात्रि में पुत्र के मंडप में ही बैठकर मतदाताओं नर्मदाप्रसाद, प्रदीपकुमार, सावित्री बाई के गणना प्रपत्र भरे और उन्हें जानकारी प्रदान की। श्री पाटर के मतदान केंद्र में कुल 642 मतदाता है जिनमें से 557 मतदाताओं के प्रपत्र इनके द्वारा डिजिटाइज किए जा चुके है। अभी तक के कार्य में श्री पाटर ने किसी भी मतदाता के प्रपत्र को बिना मैपिंग के डिजिटाइज नहीं किया है और न ही इन्होंने अभी तक किसी मतदाता को एब्सेंट,शिफ्ट या डुप्लीकेट मार्क नहीं किया है।

परिवार के सहयोग से हुआ लक्ष्य पूरा

विधानसभा क्षेत्र इंदौर तीन के मतदान केंद्र 74 कलाली मोहल्ला की बीएलओ श्रीमती प्रियंका सिलावट ने बताया कि क्षेत्र में कम शिक्षित मतदाता होने के कारण एस आई आर के बारे में ठीक से जानकारी देते हुए स्वयं उनके फार्म भरवाए। इसके बाद ऐप में एंट्री और डिजिटलाइजेशन में पटवारी तथा सुपरवाइजर के सहयोग से कार्य पूरा किया। सुबह 4:30 बजे से उठकर घर का पूरा काम कर बच्चों को स्कूल भेजने के बाद सुबह 7:30 से शाम 7:30 तक फील्ड में काम करती थी घर आकर घर का काम भी करना होता था वे लेकिन परिवार पति और देवर के सहयोग से ही इस कार्य को मैं समय से पूर्व पूरा कर पाई और गणतंत्र की मजबूती में अपना योगदान दे पाई।

पहली बार बीएलओ बने और मां की गंभीर बीमारी के बावजूद समय से पहले काम पूरा किया

शाजापुर जिले के बीएलओ श्री रवि शर्मा ने बताया कि वे नव नियुक्त बीएलओ बनाए गए उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उन्हें इस तरह के काम का कोई अनुभव नहीं था साथ ही माता जी कि गंभीर बीमारी और उपचार के लिए अहमदाबाद ले जाना।इन चुनौतियों के बाद भी श्री रवि ने एसआईआर की प्रक्रिया को ठीक से समझा और 670 मतदाताओं को फार्म वितरित कर जिन्हें कठिनाई थी उन मतदाताओं के फार्म पंचायत भवन में बैठकर भरे फिर शाम 7ः30 से एक बजे तक डिजीटल किये। इस तरह वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन एवं सहयोग से 23 नवंबर को ही शत् प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया।

इंदौर जिले की देपालपुर विधानसभा के मतदान केंद्र 64 खाड़ोतिया के बीएलओ धर्मेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि निर्वाचन कार्यालय इंदौर में प्रशिक्षण लेने के बाद तत्काल मतदाताओं को विस्तृत जानकारी देते हुए फार्म वितरण से पहले ही उनकी पूरी जानकारी फोटो आदि प्राप्त कर एक रजिस्टर मेंटेन किया और फिर फार्म प्राप्त होते ही क्रमानुसार फॉर्म जमा किसान परिवार के लोग सुबह 6 से 9 और शाम 5 से 10 तक घरों में रहते हैं इसलिए सुबह और शाम का समय इस काम के लिए चुना इसीलिए भरे हुए फॉर्म कलेक्ट कर उनका डिजिटाइजेशन पूरा करने में ज्यादा समय नहीं लगा। पंधाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्र क्रमांक 109 सैयदपुर कुल मतदाता 964 की बीएलओ श्रीमती प्रीति ठाकुर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी एस.आई.आर कार्य में शत प्रतिशत लक्ष्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के पूर्व पूर्ण कर लिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि अनुभाग पंधाना के वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उनके क्षेत्र के मतदाताओं की जागरूकता एवं सहयोग प्रदान करने से उक्त लक्ष्य प्राप्त किया है।

भारत का संविधान कानूनी दस्तावेज नहीं वह ग्रंथ है जो देश की आत्मा और लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता है : उप मुख्यमंत्री देवड़ा

विधानसभा में मनाया गया संविधान दिवस

भोपाल/नवप्रदेश। उप मुख्यमंत्री मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने कहा है कि कैलेण्डर में 26 नवम्बर की तारीख बेहद खास है। इसी दिन भारत का संविधान अपनाया गया था। हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। यह एक ग्रंथ है, जो देश की आत्मा उसके सपनों और उसके लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में शायद ही किसी देश के संविधान की मूल प्रति इतनी कलात्मक होगी। संविधान की मूल प्रति हाथ से लिखी गयी थी। यह मूल प्रति आज भी संसद भवन की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गयी है। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा बुधवार को भोपाल में विधानसभा के मानसरोवर सभागार में समारोह को संबोधित कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि संविधान का निर्माण कोई जल्दबाजी का काम नहीं था। संविधान सभा को इसे पूरा करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इस दौरान समिति की 114 दिनों की बैठकें हुईं। उन्होंने कहा कि संविधान सभा में विविधता का प्रतिबिम्ब था। कुल 179 सदस्यों मं 15 महिलाएं भी शामिल थीं। स्व. सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, दुर्गा बाई देशमुख और हंसा मेहता जैसी महिला सदस्यों ने सक्रिय रूप से सभा की बहसों में भाग लिया। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि संविधान एक स्थिर दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह समय के साथ विकसित होता रहता है। अब तक इसमें कई संशोधन हो चुके हैं, जो इसे बदलती हुई सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के अनुरूप ढालते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि आज के दिन संविधान के 78 वर्ष पूर्ण हुए हैं। उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकार और कर्त्तव्यों की व्याख्या की। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि केन्द्र और राज्य के संबंध और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय पाने के अवसर संविधान में मौजूद हैं। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है। उन्होंने संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर एवं सदस्यों को नमन किया। संविधान की ताकत का जिक्र करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि वर्ष 1940 से 1950 के बीच अनेक देश आजाद हुए, लेकिन भारत की ताकत संविधान है, इसकी वजह से हमारा देश लोकतांत्रिक देश बना हुआ है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं में 29 सदस्य मध्यप्रदेश के रहे, यह गौरव की बात है। समारोह में प्रारंभ में अपर मुख्य सचिव श्री अनुपम राजन ने कार्यक्रम के अतिथियों का स्वागत किया और संविधान की पृश्ठभूमि से सभी को अवगत कराया। कार्यक्रम में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर, नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, विधायक श्री भगवान दास सबनानी, महापौर श्रीमती मालती राय सहित विधानसभा के वरिष्ठ

दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मिलने एम्स पहुंचे पीसीसी चीफ

हिंदू संगठन ने दी भोपाल बंद की चेतावनी

भोपाल/नवप्रदेश। रायसेन के गौहरगंज में 6 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म की घटना पर राजनीतिक और सामाजिक आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। एक ओर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एम्स पहुंचकर पीड़िता के परिजनों से मिले और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी व कड़ी सजा की मांग उठाई, वहीं दूसरी ओर हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने 5 दिन में आरोपी न पकड़े जाने पर भोपाल बंद का अल्टीमेटम दे दिया है। रायसेन के गौहरगंज में वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। एक ओर कांग्रेस ने सरकार और पुलिस प्रशासन को कठघरे में खड़ा करते हुए तत्काल गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग की है, वहीं दूसरी ओर हिंदू उत्सव समिति और संस्कृति बचाओ मंच ने आरोपित की गिरफ्तारी न होने पर 5 दिनों में भोपाल बंद का अल्टीमेटम दे दिया है। घटना के बाद शहर में आक्रोश

लगातार बढ़ रहा है। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी एम्स अस्पताल पहुंचे और दुष्कर्म पीड़िता बच्ची के परिजनों से मुलाक़ात की। पटवारी ने बच्ची के स्वास्थ्य, इलाज और सुरक्षा को लेकर डॉक्टरों से विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर संभव सहायता और समर्थन परिवार को उपलब्ध कराएगी।इस दौरान पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा, मीडिया हेड मुकेश नायक, पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल, वरिष्ठ नेता रविंद्र साहू, शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनोखी पटेल, प्रदेश प्रवक्ता अभिनव बरोलिया, पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अभिषेक शर्मा सहित कई नेता मौजूद रहे।

पटवारी ने घटना पर गहरा आक्रोश जताते हुए कहा कि यह दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसा कृत्य करने वाला इंसान नहीं, राक्षस है। आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर कठोरतम सजा दी जाए, ताकि समाज को सख्त संदेश जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बच्चियों के साथ लगातार हो रही घटनाओं ने कानून-व्यवस्था की पोल खोल दी है और सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री पर निशाना साधते हुए पटवारी ने कह कि सिर्फ एसपी या टीआई हटाने से अपराध नहीं रुकते। अपराध पर नियंत्रण के लिए आधुनिक संसाधन, पर्याप्त पुलिस बल और टेक्नोलॉजी आधारित मॉनिटरिंग की जरूरत है। सरकार सिर्फ इमेज मैनेजमेंट में जुटी है।

कांग्रेस ने उठाई तीन बड़ी मांगें

1. आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस की सुनवाई।

2. महिला और बाल सुरक्षा के लिए विशेष नीति और जवाबदेही आधारित पुलिस व्यवस्था।

3.बढ़ते जघन्य अपराधों पर ठोस कार्ययोजना जारी की जाए।

एसआईआर कार्य की प्रगति की रोजाना समीक्षा करें कलेक्टर: निर्वाचन आयोग

निदेशक शुभ्रा सक्सेना और सचिव बिनोद कुमार ने वर्चुअल बैठक में दिए निर्देश

भोपाल/नवप्रदेश। भारत निर्वाचन आयोग की निदेशक श्रीमती शुभ्रा सक्सेना एवं सचिव श्री बिनोद कुमार ने बुधवार को मध्य प्रदेश के 19 जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारीऔर नगर पालिक निगमों के कमिश्नरों के साथ वर्चुअल बैठक कर विशेष गहन पुनरीक्षण (स्ढ्ढक्र) कार्य की प्रगति की व्यापक समीक्षा की। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र श्री संजीव कुमार झा भी मौजूद रहे।

निदेशक श्रीमती सक्सेना ने कहा कि जिलों में एसआईआर के कार्य को गंभीरता और प्राथमिकता से लिया जाए। उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान गणना पत्रकों के वितरण, मैपिंग, तथा डिजिटलाइजेशन की प्रगति की समीक्षा की और प्रदेश की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने भोपाल, इन्दौर और ग्वालियर के उन विधानसभा क्षेत्रों के ईआरओ से सीधे बात की जहाँ कार्य की रफ्तार अपेक्षित नहीं रही। साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे ईआरओ के कार्य की प्रतिदिन समीक्षा करें और कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार सुनिश्चित करें।

श्रीमती सक्सेना ने सभी जिलों को निर्देशित किया कि डिजिटलाइजेशन का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। बीएलओ को सहयोग देने के लिये वालेंटियर्स की नियुक्ति, तथा तीनों महानगरों में विशेष कैम्प लगाकर गणना पत्रक भरवाने की व्यवस्था के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर स्वयं मैदानी स्तर पर जाकर कार्य की स्थिति देखें और मैपिंग के कार्य को शत-प्रतिशत सटीकता के साथ पूरा कराएं।

बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने कलेक्टर्स को निर्देश दिया कि वे ईआरओ कार्य की रोजाना मॉनिटरिंग करें, तथा गणना पत्रक के डिजिटलाइजेशन का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह के भीतर सभी आवश्यक कार्य पूर्ण किए जाएँ। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया कि झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्रों में भी बीएलओ घर-घर जाकर दस्तक दें, और वालेंटियर्स मतदाताओं को फार्म भरने में आवश्यक सहयोग करें। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि एसआईआर कार्य की रफ्तार और गुणवत्ता आगामी दिनों में उनके सीधे फोकस में रहेगी।

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में संविधान दिवस मनाया

संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम

विदिशा/नवप्रदेश। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय महाविद्यालय विदिशा द्वारा संविधान दिवस पर परिचर्चा, कविता पाठ भाषण आदि गतिविधियों का आयोजन किया गया। महाविद्यालय में कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी और भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। इस कार्यक्रम में एम. ए. प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी उर्वशी सक्सेना और विकास सोनी ने संविधान पर स्वरचित कविता का पाठ किया। बी ए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी अंकित परिहार और आदित्य राज ने संविधान पर भाषण दिया। बी ए प्रथम वर्ष की छात्रा नंदनी लोधी ने संविधान पर कविता प्रस्तुत की डॉ. अजय सिंह हजारी, क्री?ा अधिकारी ने विद्यार्थियों को अपने मौलिक अधिकारों के साथ संवैधानिक मर्यादाओं को पालन करने की सीख दी। इस कार्यक्रम में संविधान के मूल्यों जैसे स्वतंत्रता, न्याय और बन्धुत्व पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में अजीज प्रेम जी फाउंडेशन से डॉ मनीष शुक्ला, श्री मोहित जी का भी सहयोग प्राप्त

हुआ। आपने संविधान से संबंधित पोस्टर और लघु कथाओं के माध्यम से संविधान के मूल्यों कर जागरूकता प्रदान की। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को समाज और पर्यावरण से जो?ने के लिए शोर्ट फिल्म भी दिखायी गई।

कार्यक्रम के संयोजक श्री भागवत सिंह पाल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान ने संविधान को भारत की आत्मा और एक जीवंत ग्रंथ के तौर पर व्याख्या की। डॉ. राज कमल प्रजापति सभी विद्यार्थियों द्वारा संविधान की उद्देशिका का वाचन कराया गया और धन्यवाद ज्ञापन दिया। इस कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ. सतेंद्र सिंह, डॉ. अजय सिंह हजारी, डॉ. सुनील कुमार जैन, डॉ. राजकुमार भीमटे, डॉ. ब्रजेश साहू, डॉ. निमिषा वर्मा, श्रीमती श्वेता सोलंकी, डॉ. राज कमल प्रजापति

राष्ट्रीय संविधान दिवस के अवसर पर 'अधिकार से पहचान-कर्तव्य से सम्मान' कार्यक्रम आयोजित

संविधान में मिले मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों की हम सबको जानकारी होना चाहिए - कलेक्टर

हरदा/नवप्रदेश। राष्ट्रीय संविधान दिवस के अवसर पर सिनर्जी संस्थान द्वारा स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 'अधिकार से पहचान-कर्तव्य से सम्मान' कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी दी गई। साथ ही सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि हमारे संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य शामिल किये गये हैं, जिनकी हम सबको जानकारी होना चाहिए और हमें इनका पालन भी करना चाहिए। इस तरह के आयोजनों के माध्यम से हम संविधान के सिद्धांतों पर चर्चा करें और इसमें प्राप्त अधिकारों और कर्तव्यों को समझें। उन्होने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देकर विद्यार्थियों को जागरूक किया जा रहा है। विद्यार्थी जनकल्याणकारी योजनाओं के जानकार रहें। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा संचालित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों एवं समस्याओं के निराकरण का प्रभावी प्लेटफार्म है। इसमें दर्ज शिकायत एवं समस्याओं का जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से अध्ययन किया जाता है एवं नियमानुसार उनका निराकरण किया जाता है।

कार्यक्रम में खेल विभाग, ई-गवर्नेंस, स्कूल शिक्षा, ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला एवं बाल विकास, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, ग्रामीण विकास विभाग, कौशल विकास एवं रोजगार, जनजातीय कार्य विभाग, कृषि विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग, एसबीआई आरसेटी, तहसील, जनपद, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, उच्च शिक्षा व जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने विभागों में संचालित योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने वाले स्टाल भी लगाये गये। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी दी गई। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।

विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह जिला चिकित्सालय ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध पर दी चेतावनी : मनमाना उपयोग रोकें

कटनी/नवप्रदेश। विश्व एंटीबायोटिक जागरूकता सप्ताह के अवसर पर जिला चिकित्सालय कटनी के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, डॉ. यशवंत वर्मा ने स्वास्थ्य सेवा से जुड़े संक्रमणों (Healthcare-Associated Infections - HAI) और एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बढ़ते स्तर पर एक गंभीर चेतावनी दी है।

अनुमानों के अनुसार 7 से 18 प्रतिशत रोगी जो या तो अस्पताल में भर्ती होते है या कोई प्रक्रिया करवाते हैं, ऐसे संक्रमण में ग्रस्त हो सकते है। इसके कारण रोगियों को न केवल जान का जोखिम उत्पन्न हो सकता है परंतु लंबी बीमारी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कमी, अन्य संक्रमण जनित शारीरिक जटिलताएं भी उसे लम्बे समय सक्रिय जीवन जीने में अक्षम बना सकती है। रोगी के परिवारजनो पर भी परिचर्या का अतिरिक्त दबाव, अनचाही आर्थिक जटिलताएं, अपने परिजन को कष्ट में देखने की पीड़ा जैसे अनचाहे कारकों से भौतिक, मानसिक व सामाजिक दशा में कमी का अनुभव करना पड़ता है। चिकित्सालय के लिये यह एक आर्थिक हानि के अतिरिक्त प्रतिष्ठा में कमी भी लाता है। राष्ट्र के लिये यह एक सक्रिय सदस्य की कमी के कारण उत्पादकता में भी कमी होती है। ऐसे समय पर संक्रमण से लड़ने एंटीबायोटिक एक मात्र हथियार उपलब्ध होता है और यदि उसमें भी असर का प्रतिरोध हो जावे तो हानि के अवसर बहुगुणित हो जाते हैं लगभग 15 प्रतिशत प्रकरण इस तरह के प्रतिवेदित किए गए हैं। यह स्थिति और विकराल रूप तब धारण करती है जब हम यह महसूस करते हैं कि वर्ष 2000 के बाद एक या दो एंटीबायोटिक ही नए अविष्कृत हुए हैं। अन्यथा हमें पूर्व में उपलब्ध दवाओं का ही सहारा लेना पड़ रहा है। कोविड के बाद इस स्थिति में लगभग तीन गुना रफ्तार से वृद्धि हो रही है। चिकित्साकीय जनित संक्रमण में ऑपरेशन के उपरान्त या शरीर में यूरिनरी अन्य कोई केन्यूला डालने या वेन्टीलेटर के उपरान्त संक्रमण शामिल है। इस तथ्य से अवगत होना ही इस प्रतिरोध को घटाने की ओर पहला कदम है। यदि हम एंटीबायोटिक का अंधाधुंध मनमाना अनियंत्रित प्रयोग रोक दें तो कई एंटीबायोटिक निष्क्रिय होने से बचाई जा सकती है।हाथ धोने के वैज्ञानिक तरीके, विसंक्रमण के सिद्धांतों का पालन, जैव रासायनिक कचरे के सुरक्षित निष्पादन, वह अन्य कदमों में हम यह निर्भरता कम कर सकते हैं। सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक ने अनुरोध किया है कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर व्यापक जागरूकता फैलाएं ताकि एंटीबायोटिक प्रतिरोध के कारण उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य संकट को टाला जा सके। इस दौरान शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. मनीष मिश्रा और आरएमओ सहित अन?य डॉक?टर्स की मौजूदगी रही।

जनसुनवाई में प्राप्त 55 आवेदनों पर हुई सुनवाई

डिण्डोरी/नवप्रदेश। कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में आज आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्याएँ और मांगें अधिकारियों के समक्ष रखीं। जनसुनवाई में कुल 55 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें मुआवजा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, पेंशन, पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मजदूरी भुगतान आदि से संबंधित प्रकरण प्रमुख रहे। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर श्री जेपी यादव, डिप्टी कलेक्टर श्री वैधनाथ वासनिक सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई के दौरान आवेदक ग्राम पंचायत हर्रा टोला

गारकामटटा निवासी 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला रामकली बाई पति स्व. श्री भूरा सिंह गोंड ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि फर्जी फौतीनामा के संबंध में पुनः जांच कराने हेतु आवेदन दिया। जिस पर कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए तुरंत अनुविभागीय अधिकारी बजाग, तहसीलदार बजाग, नायब तहसीलदार करंजिया को लिखित पत्र देकर तीन दिवस के अन्दर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार आवेदक श्रीमती अनुसुईया श्रीवास सहायक रसोइया को रमसा बालिका छात्रावास से षडयंत्र रचकर पद से हटाने के संबंध में आवेदन दिया और छात्रावास में लगे सीसी टी.व्ही कैमरे की फुटेज देखकर निष्पक्ष जांच कर पुनः रसोइया के पद पर रखने की मांग की है। जिस पर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को तलब करते हुए संबंधित की फाइल समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। और त्वरित निराकरण कर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। आवेदक श्री मोहन सिंह पाराशर सेवानिवृत्त लाइनमेन नगर परिषद डिण्डौरी ने जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत कर माह नवंबर 2010 से मार्च 2011 तक कुल 5 माह का रूका हुआ भुगतान करने की मांग की है। जिस पर कलेक्टर ने नगर परिषद अधिकारी को उक्त प्रकरण की जांच कर त्वरित शिकायत की निराकरण करने के निर्देश दिए ताकि आवेदक की समस्या का निराकरण किया जा सके।

जिला एवं तहसील न्यायालयों में संविधान दिवस का आयोजन

राजगढ़ /नवप्रदेश। संविधान दिवस के अवसर पर प्रधान जिला न्यायाधीश और अध्यक्ष श्री राजीव म. आपटे के नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणद्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रांगण में समस्त न्यायाधीशगण, कर्मचारीगणों एवं अधिवक्तागणों द्वारा संविधान की उद्देशिका का वाचन कियागया।उद्देशिका का वाचन प्रधान जिला न्यायाधीश श्री आपटे द्वारा कराया गया।इस अवसर पर संविधान की विशालता, नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्यों एवं दायित्वों पर प्रकाश डाला गया।संविधान में निहित कल्याणकारी प्रावधानों के कारण आज हमारा जीवन सुखी, संपन्न एवं समृद्धशाली है। सभी को समान न्याय का अधिकार प्राप्त है, गरीब और अमीर सभी को समान अधिकारों का लाभ प्राप्त हो रहा है।

इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश श्रीमती निवेदिता मुद्गल, जिला न्यायाधीश श्री लखनलाल गोस्वामी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती नीलिमा देवदत्त, व्यवहार न्यायाधीश सुश्री अर्चना मर्सकोले, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट सुश्री स्निग्धा पाठक, श्री सुरेश कुमार शर्मा, श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, श्री पूर्णांक चौबेसहित सचिव श्री देवदत्त उपस्थित रहे। इसी क्रम में तहसील न्यायालयों ब्यावरा, नरसिंहगढ़, सारंगपुर,

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वरिष्ठ परामर्शदाता सह एपीएस उइके ने किया पारधीढाना का निरीक्षण

बैतूल/नवप्रदेश। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के वरिष्ठ परामर्शदाता सह एपीएस श्री प्रकाश कुमार उइके बुधवार को बैतूल जिले के प्रवास पर रहे। उन्होंने वरिष्ठ समाजसेवी श्री प्रवीण ढोलके के साथ पारधीढाना, सोनाघाटी का भ्रमण कर यहां निवासरत लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। श्री उइके ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पारधी समुदाय के लोगों के आधार कार्ड, समग्र आईडी और अन्य वैध दस्तावेज प्राथमिकता से बनाए जाएं, ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि समुदाय के लोगों के लिए स्वच्छ पेयजल, बिजली, रोशनी, आवास और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। बच्चों के स्कूल में प्रवेश से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए। दौरे के बाद वरिष्ठ परामर्शदाता श्री उइके से सर्किट हाउस में बैतूल कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी और पुलिस अधीक्षक श्री वीरेंद्र जैन ने भेंट की। बैठक में पारधीढाना से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बताया कि पारधीढाना क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए पहले भी एक विशेष कैंप आयोजित किया गया था। उन्होंने आधार कार्ड, समग्र आईडी और अन्य आवश्यक सेवाओं को लेकर पुनः कैंप आयोजित करने तथा प्रत्येक कैंप के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में वरिष्ठ परामर्शदाता श्री उइके ने यह भी कहा कि पारधीढाना के सभी परिवारों के मकानों का सर्वे कर डीपीआर तैयार कर आयोग को भेजा जाए। इस पर अधिकारियों ने जानकारी दी कि प्राथमिक स्तर पर सभी परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत किए गए सर्वे में शामिल कर लिए गए हैं। दौरे के दौरान उप संचालक कृषि श्री आनंद कुमार बड़ोनिया , डिप्टी कलेक्टर श्रीमती तृप्ति पटेरिया, तहसीलदार, मुख्य नगर पालिका अधिकारीतथा विभिन्न विभागों के

कलेक्टर ने किया ओरिया मटर मंडी का निरीक्षण

कारोबार शुरू होने के पहले सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के दिये निर्देश.

जबलपुर/नवप्रदेश। कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने औरिया स्थित मटर मंडी में एक दिसम्बर से मटर का कारोबार शुरू होने के पहले यहां बिजली, पानी, साफ-सफाई और सुरक्षा के समुचित इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। श्री सिंह ने मंडी परिसर में किसानों की सुविधाओं के लिहाज से सभी जरूरी व्यवस्थायें करने की हिदायत भी अधिकारियों को दी। कलेक्टर श्री सिंह आज मंगलवार की शाम ओरिया स्थित मटर मंडी का निरीक्षण करने पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पूरे मंडी परिसर का भ्रमण किया तथा साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश अधिकारियों को दिये। श्री सिंह ने कहा कि मंडी परिसर में मटर बेचने आये किसानों को किसी भी तरह की असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाये। उन्होंने मंडी परिसर में किसानों के बैठने के लिए शेड बनाने तथा बढ़ती ठंड को देखते हुए अलाव

अथवा ब्लोअर की व्यवस्था करने कहा। कलेक्टर ने मंडी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने की हिदायत दी और पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड तैनात करने के निर्देश दिये। श्री सिंह ने किसानों द्वारा लाई गई मटर की तुलाई के लिए तीन शिफ्टों में पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को तैनात करने के निर्देश भी निरीक्षण के दौरान दिये। किसानों का किया जाये ऑनलाइन पंजीयन ~ कलेक्टर श्री सिंह ने निरीक्षण के दौरान ओरिया मटर मंडी के साथ-साथ सहजपुर मंडी में भी मटर लेकर आने वाले किसानों का ऑनलाइन पंजीयन करने की व्यवस्था प्रारंभ करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि मटर लेकर आने से पूर्व ऑनलाइन पंजीयन से कराने से किसानों के साथ-साथ व्यापारियों को भी सुविधा होगी। ऑनलाइन पंजीयन के माध्यम से किसान यह बता सकेगा कि वह किस तारीख को और कितनी मटर लेकर मंडी पहुंच रहा है। उन्होंने मंडी में मटर लेकर आने वाले वाहनों के आने और जाने के लिए अलग-अलग मार्ग तय करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये, ताकि एक साथ बड़ी संख्या में वाहन आने से जाम की स्थिति न बने। कलेक्टर के ओरिया मटर मंडी के निरीक्षण के दौरान एसडीएम अधारताल पंकज मिश्रा, उप संचालक कृषि डॉ. एस के निगम, जिला विपणन अधिकारी हिरेन्द्र रघुवंशी, मंडी बोर्ड के कार्यपालन यंत्री वीरेन्द्र सोनी तथा मंडी सचिव राजेश सैय्याम भी मौजूद थे।

प्रथम पेज का शेष

भारत को मिली कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 ...

वेन्यू के तौर पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नारणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और सरदार वल्लभभाई पटेल स्पोर्ट्स एंक्लेव को प्रस्तावित किया गया है।

कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किसी भी देश के लिए सिर्फखेल आयोजन नहीं, बल्कि उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि, विकास क्षमता, इन्फ्रास्ट्रक्चर और विजन का भी प्रतीक माना जाता है। अब तक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत, कनाडा और न्यूजीलैंड सहित कुल 9 देश इसकी मेजबानी कर चुके हैं। सबसे ज्यादा 5 बार मेजबानी का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है।

मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा...

तकनीकी विशेषज्ञता की कमी और लंबी परियोजना के लिए समयसीमा जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बिना सरकारी समर्थन के वाणिज्यिक उत्पादन फिलहाल व्यावहारिक नहीं है। इसके अलावा, खनन से जुड़े पर्यावरणीय जोखिम इस क्षेत्र को और जटिल बनाते हैं।

भारत रेयर अर्थ के लिए सप्लाई चेन विकसित करने पर कर रहा काम

संविधान दिवसः मोदी ने ...

राष्ट्र की सेवा करने के लिए सशक्त बनाया है और संसद तथा संविधान के प्रति अपने सम्मान के अनुभव साझा किए। उन्होंने वर्ष 2014 में संसद की सीढियों पर झुकने और 2019 में सम्मान के प्रतीक के रूप में संविधान को अपने माथे पर धारण करने का स्मरण किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि संविधान ने असंख्य नागरिकों को सपने देखने और उन सपनों को साकार करने की शक्ति प्रदान की है।

संविधान राष्ट्रीय अस्मिता का...

चाहते थे कि संविधान के माध्यम से हमारा सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान सुनिश्चित रहे। मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि बीते दशक में हमारी संसद ने जन-आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने के अत्यंत प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।

श्रीमती मुर्मु ने कहा कि संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए वह सभी सांसदों को बधाई देती हैं और कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से संविधान सभा के परम सम्माननीय सदस्यों की स्मृति में सादर नमन करती हैं। उन्होंने कहा कि संविधान की अंतरात्मा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे आदर्शों में अभिव्यक्त होती है।

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई

नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से नागपुर से नर्मदा प्रवाह यूनिटी मार्च यात्रा की शुरुआत हुई है , जो नागपुर से बैतूल होते हुई इंदौर पहुंची। उन्होंने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को मिलाकर जो कार्य किया वह अद्वितीय है। इसके लिए हमें विराट व्यक्तित्व के धनी सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरणा लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से प्रगति और विकास के पत्र पर आगे बढ़ रहा है। यात्रा में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास सारंग , नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, सांसद श्री शंकर लालवानी, सुश्री कविता पाटीदार, महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव, विधायक श्री मधु वर्मा, श्री महेन्द्र हार्डिया, श्रीमती मालिनी गौ?, श्री रमेश मेंदोला, श्री गोलू शुक्ला, श्री जीतू जिराती, श्री श्रवण चाव?ा, श्री सुमित मिश्रा, यात्रा प्रभारी श्री कपिल परमार आदि विशेष रूप से शामिल हुए।

उज्जैन से होने वाला प्रसारण

प्रारंभ होकर रात 11 बजे तक लगातार प्रसारण जारी रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव बुधवार को उज्जैन में आकाशवाणी उज्जैन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन भी उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उज्जैन जिले को भी सौगातें दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम से उज्जैन जिले के लिए करीब 179 करो? की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इसमें 55 करोड़ 27 लाख की लागत से महाराजवाड़ा में तैयार सांदीपनि स्कूल का एवं 30 करोड़ 21 लाख की लागत से उज्जैन रेलवे ओवर ब्रिज का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 50 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न मार्गों के निर्माण और उन्नयन कार्य, 32 करोड़ 69 लाख रुपये की लागत से शासकीय धनवंतरी आयुर्वेदिक महाविद्यालय में 250 सीटर बालक और बालिका छात्रावास का निर्माण, 8 करोड़ 37 लाख की लागत से रेप्टाइल पार्क एवं स्नेक पार्क तथा करीब 3 करोड़ की लागत से हाईटेक नर्सरी के निर्माण कार्य का भूमिपूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उपचार और इसके प्रचार-प्रसार के मामले में सिरमौर है, इसलिए उज्जैन में आयुर्वेद का एम्स बनाने की दिशा में भी हम केन्द्र सरकार को अपना प्रस्ताव भेजेंगे।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नगरवासियों को आकाशवाणी केंद्र के शुभारंभ की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह उज्जैन के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण हैं। यहां के लोगों के कान अपने आकाशवाणी केंद्र की आवाज सुनने को तरस गए थे। यह स्वप्न प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन के प्रयासों से पूरा हो रहा है। उज्जैन की हवा में बाबा महाकाल की भक्ति और शक्ति निरंतर रहती है।

किसानों की खुशहाली और

जा चुका है।मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इंदौर जिले को 264 करो? रूपए के विकास कार्यों की सौगात भी दी। इसके तहत विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इनमें इनगोरिया से देपालपुर तक मार्ग निर्माण कार्य का भूमिपूजन भी शामिल है। यह 10 मीटर चौ?ी स?क होगी, जो देपालपुर और ब?नगर विधानसभा क्षेत्रों को आपस में जो?गी।

बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवाती तूफान....

तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और अंडमान में होगी जोरदार बारिश

नई दिल्ली। उत्तर भारत में अब कड़ाके की ठंड पड़ना शुरू हो गई है। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में सर्दियों ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। वहीं, बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की स्थिति बन रही है।

अगले 24 घंटे के भीतर अंडमान सागर में मौसम अचानक करवट ले सकता है। स्काईमेट ने अगले 48 घंटों के दौरान सेन्यार चक्रवाती तूफान के टकराने के संकेत दिए हैं। इस अवधि में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हवाएं चलेंगी और बादलों के गरजने के साथ भारी बारिश दर्ज की जाएगी।आईएमडी ने 25 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच कई दक्षिणी राज्यों में भारी वर्षा की भविष्यवाणी की है। इस तूफान के कारण भारत के दक्षिणी और तटीय राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ की संभावना है। प्रभावित होने वाले प्रमुख राज्य हैं- तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र।

इन राज्यों में चलेगी शीतलहर

मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में शीतलहर चलने के साथ-साथ बर्फबारी की संभावना है, जिसका असर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक रहेगा।

दिल्ली में छाएगा कोहरा

दिल्ली में आज मौसम ठंडा रहेगा और सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है। दिन में मौसम मुख्य रूप से साफ और धूप वाला रहेगा। अधिकतम तापमान लगभग 23एष्ट से 24एष्ट के बीच रहने की उम्मीद है और न्यूनतम तापमान लगभग 8°C से 10°C तक गिर सकता है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट और अधिकतम तापमान 01 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया।

बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ हल्ला बोल, इस्तीफे की मांग

शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने उठाया झंडा

ढाका। बांग्लादेश की बर्खास्त पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सजा-ए-मौत मिलने के बाद भी उनकी पार्टी अवामी लीग ने देश के अंदर संघर्ष की राह नहीं छोड़ी है. अवामी लीग पार्टी की ओर से मंगलवार को घोषणा की गई कि वह 30 नवंबर तक पूरे देश में विरोध प्रदर्शन और प्रतिरोध मार्च आयोजित करेगी. पार्टी की ओर से यह फैसला उस समय लिया गया, जब बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल की ओर से हसीना को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। 17 नवंबर को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने 78 साल की शेख हसीना और उनके कार्यकाल के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप में फांसी की सजा दी थी. यह मुकदमा शेख हसीना की गैर-हाजिरी में हुआ, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना हुई, जबकि बांग्लादेश इसी फैसले की बिनाह पर भारत से हसीना का प्रत्यर्पण चाहता है. फिलहाल हसीना भारत में मौजूद हैं और बांग्लादेश का दावा है कि मौत की सजा पाए पूर्व गृहमंत्री कमाल भी भारत में ही छिपे हुए हैं। हसीना की पार्टी अवामी लीग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि यह फैसला मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार की साजिश है, ताकि हसीना और उनकी पार्टी को अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव से बाहर रखा जा सके।

दिल्ली बम ब्लास्ट: सफेदपोश आतंकी का सातवां मददगार शोएब गिरफ्तार

घटनाक्रम और आरोपी की भूमिका

सूत्रों के अनुसार, शोएब की गिरफ्तारी के बाद मामले की परतें खुलनी शुरू हो गई हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, शोएब को पहले भी इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और फिर छोड़ दिया गया था। हालांकि, ताजा खुलासों के बाद उसे दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

फरीदाबाद। लाल किले के पास हुए कार बम धमाके के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। एनआईए ने फरीदाबाद से शोएब नामक एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि शोएब ने आतंकी उमर नबी को धमाके से ठीक पहले न केवल पनाह दी, बल्कि लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मुहैया कराया था। इस गिरफ्तारी के साथ ही इस मामले में अब तक कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या सात हो गई है।

यह भी बताया जा रहा है कि शोएब ही मुख्य आतंकी डॉक्टर उमर को मेवात और नूंह जैसे इलाकों में ले गया था। वहां पर डॉक्टर उमर शोएब की बहन की घर ही ठहरा था।

दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर 2025 को एक कार में हुए धमाका हुआ था। इस धमाके में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के बाहर हुए कार बम धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। घटना के तुरंत बाद एनआईए ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी। ह्ढ्ढ की सघन जांच के दौरान यह बात सामने आई कि आतंकी उमर उन नबी, जो इस हमले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, को फरीदाबाद के धौज निवासी शोएब ने पनाह दी थी।

बरामदगी और एनआईए की जांच में नया अपडेट

गिरफ्तारी का यह महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब एक अन्य गिरफ्तार आरोपी, डॉक्टर मुज्जमिल ने पूछताछ के दौरान शोएब के घर का खुलासा किया। डॉक्टर मुज्जमिल की निशानदेही पर NIAने शोएब के घर से कुछ महत्वपूर्ण चीजें बरामद की हैं, जिनमें एक ग्राइंडर और अन्य सामग्रियां शामिल हैं।ू यह माना जा रहा है कि इन सामग्रियों का इस्तेमाल बम बनाने या अन्य आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा सकता था। एनआईए वर्तमान में शोएब से गहन पूछताछ कर रही है, ताकि इस आतंकी मॉड्यूल के अन्य सदस्यों और उनके नापाक इरादों का पता लगाया जा सके।

गुलामी की मानसिकता को खत्म करता है संविधान: राष्ट्रपति मुर्मू

नई दिल्ली। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बुधवार को संविधान दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि आज के दिन 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज के दिन हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था।

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, 'स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य का निर्वाहन किया। बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माता में से थे। बाबा साहब के 125 वीं जयंती के वर्ष में यानी 26 नवंबर 2015 में प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था।'

राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान राष्ट्र की पहचान की आधारशिला है और गुलामी की मानसिकता को त्यागने तथा राष्ट्रवादी सोच अपनाने का मार्गदर्शक दस्तावेज भी है।

इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने तीन तलाक, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), अनुच्छेद 370 समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि तीन तलाक से जुड़ी सामाजिक बुराई पर अंकुश लगाकर संसद ने हमारी बहनों और बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए। उन्होंने कहा कि जीसएटी के रूप में आजादी के बाद सबसे बड़ा कर सुधार देश के आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 के खत्म होने से एक ऐसी बाधा हटी, जो देश के समग्र राजनीतिक एकीकरण में बाधा बन रही थी।

पुलिस थानों में सीसीटीवी को लेकर एससी की राज्य सरकारों को चेतावनी

नई दिल्ली। पुलिस स्टेशनों में खराब पड़े सीसीटीवी कैमरों पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर को मामले पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकारों से जवाब मांगा था, लेकिन अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने के लिए 3

हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर पुलिस स्टेशनों में ष्टष्टञ्जङ्क कैमरों के काम न करने पर 3 हफ्ते में जवाब नहीं दिया गया, तो अगली सुनवाई में राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे के अनुसार, अभी तक सिर्फ 11 राज्यों ने ही सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब दिया है। वहीं, केंद्र सरकार ने भी ह्ढ्ढ जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों के संबंध में अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। केंद्र की तरफ से कोर्ट में मौजूद अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता ने अदालत से 3 हफ्ते का समय मांगा है। दरअसल 4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कस्टोडियल डेथ पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले पर कार्यवाही शुरू की थी। पिछले 7-8 महीनों में पुलिस कस्टडी में 11 लोगों की मौत हुई है।

नदी में गिरी कार पांच की मौत

बहराइच। लखीमपुर खीरी में शादी समारोह से लौट रही कार नदी में गिर गई। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई। मरने वाले सभी बहराइच के हैं। भतीजी की शादी से लौट रहे चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज के कर्मचारियों की कार मंगलवार देर रात लखीमपुर के शारदा नहर के पास सोती साइफन में गिर गई।

फिर फंसे कॉमेडियन कामरा, बीजेपी ने दी एक्शन की चेतावनी

नई दिल्ली। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इस विवाद की वजह उनकी एक टी-शर्ट है। जिसे पहनकर उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक फोटो शेयर की है। इस टी-शर्ट में कथित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी भड़क कई है और

कॉमेडियन कामरा को कड़ी चेतावनी दी है। भाजपा नेताओं ने इस पोस्ट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे अपमानजनक और भड़काऊ बताया है। वहीं, विवाद सामने आए के बाद कुणाल कामरा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया कि आरएसएस का संदर्भ देने वाली तस्वीर किसी कॉमेडी क्लब में नहीं खींची गई थी।

पुलिस कार्रवाई की चेतावनी

कुणाल कामरा के टी-शर्ट को लेकर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और मंगलवार को पुलिस कार्रवाई की चेतावनी दी है।

खेल, व्यापार एवं मनोरंजन

दुर्लभ धातुओं पर सरकार का बड़ा कदम, कैबिनेट से 7280 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज को मिली मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कुल ?19,919 करोड़ रुपये की चार बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी। इसमें ?7,280 करोड़ की दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट निर्माण योजना शामिल है, जो इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा क्षेत्र के लिए अहम मानी जा रही है। इसके अलावा, पुणे मेट्रो विस्तार के लिए ?9,858 करोड़, देवभूमि द्वारका (ओखा)-कनालस रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए ?1,457 करोड़ और बदलापुर-कर्जत तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के लिए ?1,324 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

दुर्लभ मृदा स्थायी चुम्बक योजना के लिए 7,280 करोड़ रुपये

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार

को होने वाली बैठक में दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए करीब 7,280 करोड़ रुपये का आवंटन प्रस्तावित है, जो पहले के 2,500 करोड़ रुपये के अनुमानित पैकेज से लगभग तीन गुना अधिक है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब चीन ने निर्यात नियंत्रण कड़े कर दिए हैं। चीन वैश्विक दुर्लभ पृथ्वी कच्चे माल का 60-70त्न और प्रोसेसिंग का 90त्न हिस्सा नियंत्रित करता है।

केंद्रीय सरकार ने दुर्लभ मृदा स्थायी चुम्बक निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अपनी तरह की पहली योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य सिंटर किए गए ऋश्वक्रू के उत्पादन के लिए एकीकृत विनिर्माण सुविधाएं विकसित करना है, जिसमें दुर्लभ मृदा ऑक्साइड को धातुओं में, धातुओं को मिश्रधातुओं में और आखिर में मिश्रधातुओं को तैयार चुम्बकों में बदलने की प्रक्रिया शामिल होगी। योजना पर लगभग ?7,200 करोड़ का निवेश होगा। इसके तहत 1,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MTPA) की क्षमता का सृजन और 1,200 MTPA क्षमता वाली इकाइयों की स्थापना की जाएगी। योजना की अवधि कुल 7 वर्ष होगी, जिसमें विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 2 वर्ष का समय निर्धारित है।

गुवाहाटी टेस्ट में भारत की करारी हार, 408 रन से हारी टीम इंडिया

गुवाहाटी। साउथ अफ्रीका ने गुवाहाटी टेस्ट में भारत को 408 रन से हरा दिया है। टीम ने भारत को कोलकाता टेस्ट में 30 रन से हराया था। साउथ अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत को उसके घर में क्लीन स्वीप किया है। इससे

पहले साल 2000 में दो टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से हराया था। जसप्रीत बुमराह ने पहले मैच के दौरान साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा को बौना कहा था। बरसापारा स्टेडियम में बुधवार को 549 रन का टारगेट चेज कर रही भारतीय टीम 140 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से दूसरी पारी में रवींद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की ओर से साइमन हार्मर ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए। साउथ अफ्रीका ने चौथे दिन मंगलवार को अपनी दूसरी पारी 260/5 के स्कोर पर घोषित कर दी। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत कर पहली पारी में 489 रन बनाए थे। जवाब में भारत की पहली पारी 201 रन सिमट गई थी। इस तरह भारत को टेस्ट जीतने के लिए 549 रन का टारगेट मिला था। साइमन हार्मर प्लेयर ऑफद सीरीज साउथ अफ्रीकी स्पिनर साइमन हार्मर को प्लेयर ऑफद सीरीज चुना गया। उन्होंने 2 मैच की सीरीज में 17 विकेट लिए। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को यानसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने इस मैच की पहली पारी में 93 रन बनाए और 48 रन देकर 6 विकेट झटके। यानसन को दूसरी पारी में भी एक विकेट मिला।

3 बीवियों के साथ कन्फ्यूजन और धमाल लेकर आ रहे कपिल

मुंबई। एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कपिल शर्मा की मचअवेटेड फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 का दमदार ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म धमाकेदार कंफ्यूजन, ड्रामा और हंसी के ठहाकों से भरी पड़ी है जो आपको पेट पकड़कर हंसने के लिए मजबूर कर देगी। ये ट्रेलर आपको एक झलक देगा कि कैसे कपिल शर्मा कई सारी शादियों में फंस जाते हैं। इस पागलपन के साथ, कपिल शर्मा निकाह से लेकर फेरों और गुरुद्वारे तक, हर तरह की शादी में खुद को पाते हैं। ट्रेलर का

कन्फ्यूजन और नॉन स्टॉर कॉमेडी ये वादा करती है कि 12 दिसंबर को जब फिल्म रिलीज होगी तब मनोरंजन का जबरदस्त डोज मिलने वाला है। ट्रेलर जारी करते हुए कपिल ने लिखा,÷4 पत्नियां...!! इसे घर पर ट्राई न करें, यह स्टंट हमारे एक्सपर्ट ने किया है..ष्कि सकि सकोप्यार करूं 2 सिनेमाघरों में 12 दिसंबर 2025 को।÷ इसके ट्रेलर को देखकर पता चल रहा है कि तीन बीवीयों वाले कपिल चौथी बीवी की तलाश में हैं। इस ट्रेलर की शुरुआत में कपिल साफ कहते हुए दिख रहे हैं,'एक लड़की से प्यार करता हूं, उसके लिए हिंदू से मुसलमान बना और मुसलमान से क्रिश्चियन बना लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं मिली। बल्कि तीनों धर्मों से एक-एक बीवी मिल गई फादर।' यानी साफहै कि कपिल की जिंदगी में ढेर सारा तूफान आने वाला है।

एचडीएफसी बैंक, कांतार ब्रांड्स की इंडिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड्स 2025 की लिस्ट में नंबर 1 पर

मुंबई। भारत के लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक, एचडीएफसी बैंक को कांतार ब्रांड्स की टॉप 100 सबसे वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड माना गया है। यह वैल्यूएशन बैंक के डिजिटल इनोवेशन और कस्टमर-सेंट्रिक स्ट्रेटेजी के प्रति कमिटमेंट की वजह से है। एचडीएफसी बैंक की ब्रांड वैल्यू 2024 में 38.3 बिलियन डॉलर से 18 परसेंट बढ़कर 44.9 बिलियन डॉलर हो गई। 2014 में जारी पहली ब्रांड्स इंडिया रिपोर्ट के बाद से इसमें 377 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के 12 सालों में से आठ सालों में बैंक को नंबर 1 रैंक मिला है। अपने एडिटोरियल में कांतार ने कहा, ÷एचडीएफसी बैंक की ग्रोथ लगातार इनोवेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट से हुई है, जिसमें विजिल आंटी का लॉन्च भी शामिल है।

खेल प्रतिभाओं को मिलेगा मंच ताकि वे देश के लिये खेल सकें- मुरूगन

केन्द्रीय सूचना, प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री एल. मुरूगन के मुख्य आतिथ्य में हुआ सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ

कटनी, पन्ना, छतरपुर में खेल सुविधाओं के विकास में कमी नहीं आने दी जायेगी- सांसद श्री शर्मा

कटनी/नवप्रदेश। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के खेलो इंडिया और फिट फॉर युवा विकसित भारत अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंगलवार को कटनी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेल मैदान (फॉरेस्टर मैदान) में सांसद खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। केन्द्रीय सूचना, प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री एल. मुरूगन के मुख्यातिथ्य और वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार के विशेष आतिथ्य और खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा के संयोजन में सांसद खेल महोत्सव का शानदार आगाज हुआ। रंग-बिरंगी आतिशबाजी और उत्सवी माहौल में स्कूली छात्र-छात्राओं के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जो अगले एक माह तक सतत रूप से जारी रहेगा। कार्यक्रम के दौरान विधायक सर्व श्री संजय सत्येन्द्र पाठक, संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल, प्रणय प्रभात पांडेय, धीरेन्द्र बहादुर सिंह, अरविंद पटेरिया, बृजेन्द्र प्रताप सिंह, प्रहलाद लोधी सहित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाडी केदार जाधव, अंतर्राष्ट्रीय तैराक सत्येन्द्र सिंह लोहिया, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक टंडन सोनी, महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता मेहरा, नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक, पुलिस

अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा, जिला पंचायत सीईओ हरसिमरनप्रीत कौर, नगर निगम आयुक्त सुश्री तपस्या परिहार, पूर्व विधायक अलका जैन, पूर्व जिलाध्यक्ष पीताम्बर टोपनानी, रामरतन पायल, रामचंद तिवारी, चमनलाल आनंद, पूर्व महापौर शशांक श्रीवास्तव, सुरेश सोनी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, गणमान्य नागरिकों सहित बड़ी संख्या में खिलायिों की उपस्थिति रही।गांवों की खेल प्रतिभाओं को खेल महोत्सव से मिलेगा मंच- केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री मुरूगन केन्द्रीय सूचना, प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री एल मुरूगन ने सांसद खेल महोत्सव को मुख्य अतिथि की हैसियत से संबोधित करते हुये कहा कि सांसद श्री बीडी शर्मा ने भव्य एवं विशाल खेल महोत्सव का आयोजन किया है। जो एक माह तक चलेगा। इसके लिये 75 हजार युवाओं ने पंजीयन कराया है। जो किसी भी संसदीय क्षेत्र में सर्वाधिक है। उन्होंने इस महोत्सव में प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनायें देते हुये कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच खेलो इंडिया के माध्यम से सांसद खेल महोत्सव का आयोजन गांव-गांव की युवा खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करेगा। उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री के संकल्प का जिक्र करते हुये युवाओं को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के विकसित और मजबूत भारत बनाने के मिशन को फलीभूत करने में युवाओं की बड़ी भूमिका का उल्लेख किया। केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत अगले 25 साल में विश्व का नेतृत्व करेगा।खेल सुविधाओं में कमी नहीं आने दी जाएगी- सांसद श्री शर्मा खजुराहो सांसद श्री व्ही.डी शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि सांसद खेल महोत्सव में लगभग 75 हजार खिलाडियों का पंजीयन किया जा चुका है। खेलो इंडिया के तहत कटनी से प्रारंभ हो रहे खजुराहो लोकसभा के सांसद खेल महोत्सव में गांव-गांव के खिलाडियों की सहभागिता के प्रयास किये जाएंगे। ताकि वे अपने खेल का प्रदर्शन कर खेल प्रतिभा को निखार सकें। सांसद श्री शर्मा ने कहा कि कटनी, पन्ना एवं छतरपुर के खिलायिों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए खेल मैदानों का विकास कार्य निरंतर जारी है। इन कार्यो में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आनें दी जाएगी, ताकि यहां खेल रहे कई युवा आने वाले समय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले, प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। सांसद श्री शर्मा ने विधायक मुड़वारा श्री जायसवाल के आग्रह पर करीब साढ़े 7 करोड़ की लागत से प्रस्तावित मल्टीपरपज हाल के निर्माण के लिये केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री श्री मुरूगन द्वारा 1 करोड़ रूपये और स्वयं उनके द्वारा भी सांसद निधि से 1 करोड़ रूपये देने की घोषणा की।खिलाडियों की प्रतिभा को निखारनें निरंतर हो रहे विकास कार्य - विधायक श्री जायसवाल विधायक मुवारा श्री संदीप जायसवाल नें कहा कि प्रधानमंत्री की मंशानुरूप सांसद खेल महोत्सव में अनेक खेलों को शामिल

न्यूज गैलरी

विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों में 01 दिसम्बर से 05 दिसम्बर तक धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

भोपाल/नवप्रदेश। पुलिस आयुक्त,भोपाल श्री हरिनारायणचारी मिश्र ने मध्यप्रदेश की षोडश (16वीं) विधानसभा के षष्ठम सत्र 01 दिसम्बर 2025 से 05 दिसम्बर 2025 के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेश अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। इस प्रकार एकत्रित भीड़ गैर कानूनी भीड़ समझी जाएगी। कोई व्यक्ति किसी जुलूस/प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा और न ही कोई सभा आयोजित करेगा। कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डण्डा, भाला, पत्थर, चाकू अन्य धारदार हथियार या आग्नेय शस्त्र साथ लेकर नहीं चलेगा। सत्रावधि के दौरान विधानसभा परिसर के 5.00 किलोमीटर की परिधि में भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रेक्टर-ट्राली, डम्फर एवं धीमी गति से चल यातायात बाधित करने वाले तांगा, बैल-गाड़ी इत्यादि के आवागमन पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसके फलस्वरूप शिक्षण संस्थाओं, होटल, दुकान, उद्योग एवं निजी अथवा सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो। यह आदेश ड्यूटी पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश 01 दिसम्बर 2025 से 05 दिसम्बर 2025 तक प्रातः काल 06ः00 बजे से रात्रि 12ः00 बजे तक अथवा विधानसभा सत्र का सत्रावसान/स्थगित होने तक, जो पहले हो, निम्नलिखित मार्ग/क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा।

लिली टॉकीज से 7वीं बटालियन के सामने वाला मार्ग, एम.व्ही.एम. कॉलेज, एयरटेल तिराह से रोशनपुरा पहुंचने वाला मार्ग। बाणगंगा चौराहा से जनसंपर्क कार्यालय से लोअर लेक मार्ग से राजभवन से ओल्ड विधानसभा चौराहा की ओर जाने वाला मार्ग। जिंसी चौराहा से पुराना सी.आई.डी. रेल अधीक्षक कार्यालय से शब्बन चौराहा होते हुए पुरानी जेल की ओर जाने वाला मार्ग। स्लाटर हाउस रोड, मैदामिल से बोर्ड ऑफिस चौराहा। झरनेश्वर मंदिर चौराहे से ठण्डी सड़क, ठण्डी सड़क से 74 बंगले के सबसे ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा। पॉलिटेकनिक रोड/दूरदर्शन रोड भारत भवन रोड से माननीय मुख्यमंत्री निवास तक। नवीन विधानसभा क्षेत्र से राजभवन क्षेत्र, मुख्यमंत्री निवास क्षेत्र, रोशनपुरा चौराहा से पत्रकार भवन एवं राजभवन की ओर जाने वाले समस्त मार्ग, विधायक विश्राम गृह के सामने वाला रोड, मैदा मिल सड़क के उपर का समस्त क्षेत्र, बोर्ड ऑफिस चौराहा, 74 बंगला, ओमनगर, वल्लभ नगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र, पत्रकार भवन, नवीन विधानसभा की ओर पहुंचने वाली सड़क, सतपुडा भवन, विन्ध्यांचल भवन, वल्लभ भवन एवं अरेरा एक्सचेंज का क्षेत्र नीलम पार्क थाना जहांगीराबाद, शाहजहाँनी पार्क थाना तलैया, अम्बेडकर पार्क थाना टीटी नगर, चिनार पार्क थाना एम0पी0नगर। इस आदेश के प्रभावशील रहने की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्रों में आम सभा, पुतला दहन, धरना प्रदर्शन, आंदोलन, रैली नहीं करेगा। यह आदेश विवाह समारोह, बारात तथा शवयात्रा पर प्रभावशील नहीं रहेगा।

अध्यक्ष म.प्र. राज्य सफाई कर्मचारी आयोग प्रताप करोसिया ने सफाई व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की दिए निर्देश

राजगढ़/नवप्रदेश। अध्यक्ष म.प्र. राज्य सफाई कर्मचारी आयोग श्री प्रताप करोसिया (केबिनेट मंत्री दर्जा) ने जिले की सफाई व्यवस्था, श्रमिकों के हितों और स्वच्छता प्रबंधन को लेकर विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सभी सफाई कर्मियों की ईपीएफ कटौती, स्वीकृत एवं संविदा पदों की संख्या, तथा दैनिक वेतन भोगियों के कार्य व अवकाश की स्थिति की गहन समीक्षा की गई। स्वास्थ्य विभाग व जिला अस्पताल में सफाई कर्मियों से संबंधित शिकायतों को भी संज्ञान लिया गया। साथ ही जिले में संचालित स्वच्छता परिसरों की संख्या, उनकी स्थिति और आवश्यक सुधारों पर चर्चा की गई।

अध्यक्ष म.प्र. राज्य सफाई कर्मचारी आयोग श्री करोसिया ने कहा कि ÷सर पर मैला ढोना अपराध है और प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों को सफाई कर्मचारियों के हित में बेहतर योजनाएँ लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही नगरीय निकाय अपनी अच्छी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करें। सफाई कर्मियों को प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर बढ़ाएँ। परिवारों की आर्थिक मजबूती और समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के निर्देश।

नालों की सफाई की समीक्षा करते हुए नालों की सफाई में कितने उपकरण लगते हैं, इसकी जानकारी स्वच्छता निरीक्षक से ली गई। अध्यक्ष म.प्र. राज्य सफाई कर्मचारी आयोग श्री करोसिया ने कहा कि सफाई कार्य पारदर्शी और समयबद्ध हो।मैन्युअली मैला उठाने पर पूर्ण प्रतिबंध। उन्होंने कहा कि 20 हजार वर्गफीट में महार्षि वाल्मीकि सामुदायिक भवन बनाने के निर्देश बैठक में दिए गए। यह भवन सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में उपयोग होगा।सफाई कर्मियों के सुझाव बैठक में मौजूद सफाई कर्मियों के प्रतिनिधियों से सुझाव लिए और उन्हें कार्ययोजना में शामिल करने का भरोसा दिया।

अध्यक्ष म.प्र. राज्य सफाई कर्मचारी आयोग श्री करोसिया ने निर्देशित किया कि शहरी क्षेत्रों में सफाई कामगार जो काफी समय से मकान बना कर रह रहे हैं। उन्हें स्वामित्व का प्रमाण दिया जाए। यह प्रमाण नगरीय प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। छात्रावासों एवं शासकीय उपक्रमों में सफाई कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम समान होना चाहिए। अनुग्रह सहायता राशि की व्यवस्थित गणना कर प्रभावित परिवार को दी जाए। साथ ही संविदा कर्मियों की सुरक्षा अवकाश एवं अवकाश नगदीकरण उचित रूप में हो। साथ ही बैठक में कचरा प्लांट बनाना, बायो संयंत्र निर्माण, सफाई में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल एवं वाल्मिकी समाज के युवाओं के रोजगार के लिए नवाचार पर प्रभावी चर्चा की गई।

कॉन्ट्रैक्टर पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश

कई ठेकेदार कलेक्टर रेट पर मजदूरी का भुगतान नहीं कर रहे हैं, इसे तुरंत ठीक किया जाए। अनुबंध की सभी शर्तों को ठेकेदार को स्पष्ट रूप से बताएं। शर्तें पूरी न होने पर कठोर कार्रवाई होगी। सीएमओ को इस संबंध में नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। जिनमें बोडा, तलेन, सारंगपुर, खिलचीपुर, जीरापुर को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर रजनी सिंह की अध्यक्षता में गन्ना पेराई सत्र 2025-26 की बैठक सम्पन्न

गन्ना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय सीमा में किसानों को भुगतान हो

नरसिंहपुर/नवप्रदेश। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह की अध्यक्षता में गन्ना पेराई सत्र 2025-26 की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बुधवार को अधिकारियों, गन्ना मिल प्रबंधकों एवं कृषक संघों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्रीमती सिंह ने निर्देशित किया कि गन्ना उत्पादक किसानों को शुगर मिल में गन्ना प्रदाय करने के लिए पर्ची सिस्टम का कड़ाई से पालन किया जावे, कृषक पर्ची के माध्यम से ही गन्ना प्रदाय करेंगे तथा डिस्प्ले सिस्टम के माध्यम से प्रचलित टोकन का प्रदर्शन किया जाए। किसानों को एसएमएस द्वारा पर्ची की जानकारी दी जाए। शक्ति शुगर मिल कौंड़िया द्वारा उपयोग किए जा रहे एप से कृषक काफी लाभांवित हुए हैं, जिसमें किसानों को भुगतान की जानकारी एप के माध्यम से प्रदर्शित हो रही है और सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी है। शुगर मिल गेट पर डिस्प्ले के माध्यम से ट्राली की तुलाई की जानकारी दी जाए। शुगर मिल परिसर में यार्ड की क्षमता वृद्धि हो, ताकि रोड पर ट्रालियां न लगे एवं यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। शुगर मिलों में किसानों के लिए पेयजल और शौचालय आदि की व्यवस्था की जाए और मिल परिसर में स्वच्छता के मानकों का पालन किया जाए। समस्त गन्ना ट्रालियों में रेडियम रिफ्लेक्टर लगवाना सुनिश्चित करें, ताकि रात्रि समय में दुर्घटनाओं को रोका जा सके। शुगर मिलों में जेसीबी मशीन हमेशा तैयार रहे, ताकि रोड पर किसी भी प्रकार से जाम न लग सके। मिल गेट और बाहर गार्ड द्वारा व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित रहे। तौल- कांटा की टेस्टिंग किसानों की उपस्थिति में की जाए और पंचनामा तैयार किया जाए। नाप-तौल अधिकारी द्वारा समय- समय पर औचक निरीक्षण कर तौल-कांटे की जांच की जाए।

बैठक में कलेक्टर श्रीमती सिंह ने निर्देश दिए कि शुगर मिलों द्वारा गन्ना किसानों को उनके गन्ने का भुगतान गन्ना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय सीमा में बैंक खातों में किया जाए। शुगर मिलों द्वारा क्रय किए गए गन्ना की मात्रा, राशि, गन्ना मूल्य भुगतान एवं कृषक संख्या संबंधी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक शुक्रवार को प्रस्तुत करें और किसानों की समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाए। रिकव्हरी की टेस्टिंग पूर्णतः पारदर्शी रूप से किसानों की उपस्थिति में की जावे। समस्त शुगर मिल गन्ना मूल्यों में एक रूपता रखने के निर्देश शुगर मिलों को दिए। दिसम्बर माह के प्रारंभ सप्ताह में शुगर रिकव्हरी जांच के निर्देश दिए। गन्ना ट्रालियां ओव्हरलोड होकर नहीं चलाई जाए और सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखा जाए। कलेक्टर ने सहायक संचालक गन्ना को निर्देशित किया कि वे उक्त सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन करवाना सुनिश्चित करें और समय- समय पर शुगर मिलों में आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जाए। बैठक में सहायक संचालक गन्ना डॉ. अभिषेक दुबे ने पेराई सत्र 2025- 26 की कार्ययोजना प्रस्तुत की। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री गजेन्द्र सिंह नागेश, उप संचालक कृषि श्री मोरिस नाथ, सहायक संचालक गन्ना डॉ. अभिषेक दुबे, जीएमडीआईसी श्री पंकज सिंह पटेल, जिला परिवहन अधिकारी, गन्ना अनुसंधान केन्द्र बोहानी के वैज्ञानिक, शुगर मिल प्रबंधक और कृषक संघों के प्रतिनिधि मौजूद थे।

संविधान दिवस : संविधान की उद्देशिका का किया सामूहिक वाचन

स्कूलों में आयोजित ऑनलाइन संविधान दिवस क्विज प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने हिस्सा

बैतूल/नवप्रदेश। जिले में संविधान दिवस 26 नवम्बर को मनाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रातः 11 बजे से आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अक्षत जैन, संयुक्त कलेक्टर श्री मकसूद अहमद सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन भी किया गया। तत्पश्चात संविधान पर केंद्रित फिल्म को देखा गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जैन ने कहा कि संविधान दिवस हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों, कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति नागरिकों को जागरूक करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर 1949 के दिन, भारतीय संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अंगीकृत किया और 26 जनवरी, 1950 को इसे लागू किया गया, जिससे भारत को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। वर्ष 2015 में भारत सरकार ने 1949 में भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के सम्मान में औपचारिक रूप से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। तब से प्रत्येक वर्ष इस दिन, राष्ट्र संविधान को अंगीकृत किए जाने, संविधान की प्रस्तावना, अपने संविधान को जानें, संविधान का निर्माण और संविधान की महिमा का उत्सव मनाया जाता है।

स्कूलों और कॉलेज में विशेष सभा आयोजित

संविधान दिवस के अवसर पर तहसील, पंचायत व ग्राम स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में समस्त स्कूलों और कॉलेज में विशेष सभा आयोजित की गई, जिसमें भारतीय संविधान के अनुठे स्वरूप, संविधान सभा का महत्व एवं योगदान, संविधान सभा की महिला सदस्यों के योगदान पर विशेष चर्चा की गई। साथ ही ऑनलाइन संविधान दिवस क्विज प्रतियोगिता में भी विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।

जिला न्यायालय में संविधान की प्रस्तावना का किया गया सामूहिक वाचन

न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया गया पुरस्कृत

रायसेन/नवप्रदेश। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार सोहाने के मार्गदर्शन एवं अध्यक्षता में 26 नवम्बर 2025 को संविधान दिवस के उपलक्ष्य में जिला न्यायालय परिसर रायसेन में जिला न्यायालय के समस्त न्यायाधीषगण एवं न्यायालयीन अधिकारी व कर्मचारीगण द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। साथ ही संविधान दिवस के अवसर पर जिला न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में प्रधान जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में विधिक साक्षरता शिविर सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय श्री अरविन्द कुमार जैन द्वारा संविधान दिवस के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि 26 नवंबर, हम भारतीयों के लिए अत्यंत गौरव और सम्मान का दिन है। इसी दिन वर्ष 1949 में

भारत की संविधान सभा ने हमारे महान भारतीय संविधान को अंगीकार किया था। यह वही संविधान है जिसने हमारे देश की नींव को मजबूत बनाया और हमें एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य का दर्जा दिया। भारत का संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की विविधता, संस्कृति और मूल्यों का प्रतिबिम्ब है। कार्यक्रम में न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह (दिनांक 09 नवम्बर 2025 से 14 नवम्बर 2025) के तहत आयोजित मैराथन प्रतियोगिता एवं चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्री अनिल कुमार सोहाने द्वारा शील्ड एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। मैराथन प्रतियोगिता में बालिका वर्ग से प्रथम स्थान शोभा भील, खेल परिसर रायसेन द्वितीय स्थान शालिनी मालवीय ताईक्वांडो क्लब रायसेन, तृतीय स्थान नंदीनी, पी.एम श्री महाविद्यालय रायसेन एवं मैराथन प्रतियोगिता में बालक वर्ग से प्रथम स्थान पुष्पेन्द्र दांगी, द्वितीय स्थान सत्यम पवार व तृतीय स्थान राज कुषवाह, खेल परिसर रायसेन द्वारा प्राप्त किया गया। इसी तरह दिनांक 14 नवम्बर को सांदीपनि विद्यालय पाठनदेव में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कामना सेन कक्षा 11 (विज्ञान संकाय), द्वितीय स्थान खुशबु रैकवार, कक्षा 11 (विज्ञान संकाय),

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक यशवंत धोटे द्वारा हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित एवं फ्लैट नंबर 402 , कौशल्या विहार , नेपियर टाउन , 482001 से प्रकाशित, मो. 6262188999 (न्याय क्षेत्र जबलपुर) ।